लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 16 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 318

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के 'रेप की कोशिश' फैसले पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- Research में रही बड़ी कमी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाने से पहले पूरी तरह से रिसर्च न किए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट को बताया गया कि पटना हाई कोर्ट ने माना था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना और उसकी छाती दबाकर शारीरिक छेड़छाड़ करना 'रेप की कोशिश' का अपराध नहीं माना जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि वह पटना हाई कोर्ट के हालिया फ़ैसले की समीक्षा करके एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। मंगलवार को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फ़ैसले पर स्वत : संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा खोलना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना 'रेप की कोशिश' के अपराध के दायरे में नहीं आता है। भारतीयनौसेना जानकारी सुनवाई के दौरान, बेंच ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट को मंज़ूरी दी, जिसमें यौन अपराध के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को निर्देश दिया कि वे उसके द्वारा मंज़ूर की गई हैंडबुक या गाइडलाइंस में इस्तेमाल किए गए शब्दों का सख्ती से पालन करें। इससे पहले इस साल, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी को निर्देश दिया था कि वह यौन अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता और सहानुभूति लाने के लिए व्यापक गाइडलाइंस का ड्राफ़्ट तैयार करे। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे नियम भारत के सामाजिक ताने-बाने को दर्शाने वाले होने चाहिए, न कि विदेशी कानूनों से लिए गए हों।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मिला स्थान

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। यहाँ की प्रसिद्ध और सदियों पुरानी भैरव यात्रा को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इस गौरवशाली मान्यता पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी प्रशासन और जम्मू-कश्मीर के संस्कृति विभाग को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी है और इसे गौरव का क्षण बताया है। भारतीयनौसेना जानकारीराजौरी की भैरव यात्रा एक प्राचीन परंपरा है, जो हर साल होली के त्योहार से ठीक पहले सीमावर्ती जिले के मुख्य बाजारों में एक भव्य शोभायात्रा के रूप में निकाली जाती है। भगवान काल भैरव को समर्पित यह जीवंत उत्सव क्षेत्र की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को अपने भीतर समेटे हुए है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे राजौरी के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित मान्यता क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और इसके उत्सव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, कोई चुनौती नहीं: योगी आदित्यनाथ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस-2026 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सम्मानित किया। बुधवार को इस सम्मान समारोह में उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रशिक्षित युवाओं से संवाद किया और उनके उत्पादों की सराहना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार था और न पारदर्शी भर्ती प्रणाली। सरकारी नौकरियों पर एक परिवार का अधिकार था और बिना पैसे कोई काम नहीं होता था।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकार की सोच व कार्यशैली बीमार थी। 2017 से पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन थी। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने नौ लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सवा तीन करोड़ से अधिक युवा व कारीगर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े हैं।

स्किल डेवलपमेंट को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार देश में कौशल विकास मंत्रालय का गठन कर स्किल डेवलपमेंट को नई पहचान और दिशा दी। इसे युवाओं के रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। करीब दस वर्ष पहले यहां मौजूद अधिसंख्य युवा छात्र थे और माता-पिता पर निर्भर थे। तब प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। स्कूल शिक्षा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी और युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। कानून-व्यवस्था की स्थिति भी कमजोर थी। न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी और न ही आम नागरिक।

'साझा भविष्य के लिए कौशल'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष यूनेस्को ने विश्व युवा कौशल दिवस की थीम ₹साझा भविष्य के लिए कौशल₹ निर्धारित की है। अवसर तभी साकार होते हैं, जब दूरदृष्टि और सकारात्मक सोच वाली सरकार हो। दुनिया का सबसे अधिक युवा वर्ग उत्तर प्रदेश में है और यह गर्व का विषय है।

यह हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम इस स्केल को स्किलिंग से जोड़कर यूपी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा शक्ति किसी भी चुनौती का समाधान बन सकती है। युवाओं को सही दिशा, प्रशिक्षण व अवसर मिलें तो वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

पहले यूपी के नाम से चिढ़ते थे बाहरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने ऐसे हालात बना दिए कि बाहर के लोग यूपी के नाम से चिढ़ते थे। कोई युवा डिप्लोमा या डिग्री लेकर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसे अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सरकारी नौकरियों पर एक खानदान का अधिकार था, पारदर्शिता का अभाव था। उत्तर प्रदेश में पहले भर्ती प्रक्रियाओं में भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार हावी था। बिना पैसे कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल दो ही खाता है। जिसके पास सीमित आवश्यकता है, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वह ठीक से सो भी नहीं पाता। उसके लिए तो जीवन नर्क से बदतर है।

सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत पर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल, 'लिक्विड डाइट' और मेडिकल मदद की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिए तुरंत मेडिकल मदद की मांग की गई है। वांगचुक, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के उस विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कथित NEET परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ किया जा रहा है। लाइव-लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वकील राकेश कुमार सैनी ने यह याचिका दायर की है। इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार से मांग की गई है कि वांगचुक को तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए और अगर ज़रूरत हो, तो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती लिक्विड डाइट दी जाए। बुधवार को CJP का विरोध-प्रदर्शन 25वें दिन में और वांगचुक की भूख हड़ताल 18वें दिन में प्रवेश कर गई। संगठन ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन, यानी 20 जुलाई को चलो संसद मार्च निकालने की भी घोषणा की है और समर्थकों से मिस्ड-कॉल कैंपेन के ज़रिए रजिस्टर करने की अपील की है। हालांकि बुधवार को यह याचिका चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच के सामने लिस्ट की गई थी, लेकिन HT को पता चला है कि वकीलों के काम से दूर रहने की वजह से सुनवाई गुरुवार तक टाल दी गई है। याचिका में खास तौर पर अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे '....उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाएं और उन्हें लिक्विड डाइट के ज़रिए ज़रूरी पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल ज़बरदस्ती दें, जो इंसानी शरीर के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं और साथ ही वांगचुक की जान और सेहत की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकन से जुड़े विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह सुधार के लिए किए जा रहे उपायों की पूरी जानकारी दें। एक सप्ताह बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी। एक छात्र की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, 'युवा छात्रों में बहुत निराशा है। इसे देखा जाना चाहिए।' बेंच के सदस्य जोयमाल्या बागची ने कहा, 'व्यवस्था में कुछ समस्याएं धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं कि उनके समाधान में आप हमारी सहायता करें।'

कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि इस छात्र की व्यक्तिगत मार्कशीट से जुड़े

मुद्दों को सुलझा लिया गया है। मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।

पिछले महीने OSM प्रणाली में सामने आई समस्याओं की जांच के लिए एक सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया था। कमिटी को तकनीकी खामियों के कारण मूल्यांकन में हुई दिक्कतों की जांच करने को कहा गया है। साथ ही उसे OSM सिस्टम की खरीद प्रक्रिया और टेंडर शर्तों की समीक्षा का ज़िम्मा भी दिया गया है।

मूल्यांकन की गड़बड़ियों के सामने आने के बाद सीबीएसई में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। इसके तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया। अब मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी दखल दिया है। कोर्ट के रुख को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया कि उन्हें कमिटी और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देने का अवसर दिया जाए।

खतरे में देश की परमाणु सुरक्षा! भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम के डेटा में सेंध

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु स्थित देश के सबसे बड़े कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी संवेदनशील डेटा लीक हो गई है। वर्ल्ड लीक्स नाम के दो हैकर ग्रुप ने इस पावर प्लांट की जानकारियों को पोस्ट किया है, जिसमें प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट (नक्शे), सप्लायर्स की जानकारी, मीटिंग और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, उपकरणों के रिव्यू और इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े करीब 19,000 जरूरी दस्तावेज की डिटेल शामिल है। वर्ल्ड लीक्स हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि ये दस्तावेज अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के हैं, जो इस प्लांट में कॉन्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा है। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के सात परमाणु संयंत्रों में सबसे बड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने बताया कि उसके डेटा में आंशिक सेंधमारी की गई है। कंपनी ने बताया कि यह डेटा थर्ड पार्टी डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर योट्टा के सर्वर पर होस्ट था। रिलायंस ने इस घटना की जानकारी भारत सरकार को दे दी है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि किस तरह का डेटा चोरी हुआ है। परमाणु सुरक्षा संबंधी मामलों में सरकारों को सलाह देने और देशों की तैयारियों का आकलन करने वाली संस्था न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रोथ ने कहा कि डेटा लीक से प्लांट की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस तरह की घटना ने कंपनियों पर सवाल खड़ा कर दिया है कि वे इन खतरों से निपटने में कितने सक्षम हैं।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा, पुलिस रिमांड पर भेजे गए

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कानून के छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने, अभद्र व्यवहार करने और सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रबल प्रताप सिंह और चंदर भान के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर-13 में एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप सिंह ने खुद को याचिकाकर्ता बताकर पेश किया। इस दौरान उसने कथित तौर पर अदालत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कागज फेंके और न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। जब कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के साथ धक्का-मुक्की भी की। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दोनों आरोपियों का आईएचबीएएस (IHBAS) में मेडिकल परीक्षण कराया गया। डॉक्टरों ने अपनी जांच में बताया कि दोनों को तत्काल किसी मानसिक उपचार की आवश्यकता नहीं है। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से आपत्तिजनक शब्दों वाले कुछ पर्चे भी बरामद किए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन पर्चों का उद्देश्य क्या था और क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश या योजना थी।

चिन्नास्वामी भगदड़ मामला: पूर्व पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को क्लीन चिट

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जून 2025 में हुई भगदड़ मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूर्व पुलिस आयुक्त बी. दयानंद समेत तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच समाप्त करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। 4 जून 2025 को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ऐतिहासिक खिताबी जीत के जश्न के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे।

क्वांटम तकनीक में डीआरडीओ की बड़ी सफलता, सेना का कम्यूनिकेशन नेटवर्क होगा पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तकनीक से भारतीय सेना का कम्यूनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। इसे क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन (QKD) कहते हैं। डीआरडीओ ने इसके सैन्य फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिए हैं। यह सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है, जो क्वांटम युग में आने वाले नए साइबर हमलों से देश के संचार की अच्छी तरह रक्षा कर सकता है। यह तकनीक फाइबर केबल्स के जरिए संदेश भेजने का बहुत आधुनिक और सुरक्षित तरीका है। डीआरडीओ की टीम ने अपनी लैब में की गई टेस्टिंग और पिछले अनुभव का फायदा उठाते हुए बेंगलुरु की कंपनी Taqbit Labs के साथ मिलकर यह उन्नत सिस्टम तैयार किया है। इसका मकसद देश के अहम नेटवर्क को मजबूत सुरक्षा प्रदान करना है। फाइबर केबल से सुरक्षित संदेश भेजने वाली स्वदेशी क्वांटम तकनीक का फील्ड ट्रायल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक शानदार उपलब्धि है।

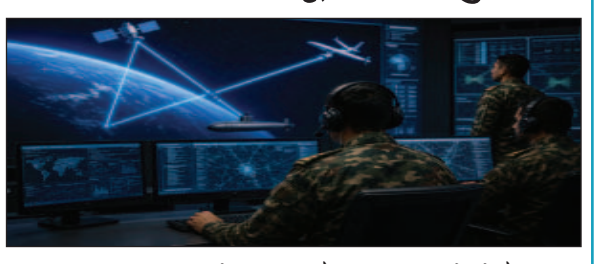

इससे भारतीय सेना का संचार नेटवर्क अब हैकिंग से पूरी तरह सेफ रहेगा। इस तकनीक से सेना के मैसेज और गुप्त जानकारियों को हैक करना या चुराना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन देश या कोई भी हैकर देश के सैन्य नेटवर्क में सेंध नहीं लगा पाएगा। डीआरडीओ और IIT दिल्ली ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फ्री-स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफल परीक्षण किया था। यह तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, जो बैंकिंग, मेडिकल और डिफेंस सेक्टर के गोपनीय डेटा को हैकर्स से सुरक्षित रखेगी।

वाराणसी को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! गंगा और वरुण नदी के किनारे ₹25,446 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वाराणसी के बुनियादी ढांचे को एक नया और ऐतिहासिक आयाम देने वाले बड़े रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध काशी नगरी को ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से परमानेंट मुक्ति दिलाने के लिए गंगा और वरुण नदियों के किनारे कुल 89 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को आधुनिक 'हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल' (HAM) के तहत तैयार किया जाएगा। यह एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल है जिसका उपयोग भारत सरकार, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), बड़े एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में करती है। इसके निर्माण से शहर के आंतरिक मार्गों पर वाहनों का भारी दबाव बेहद कम हो जाएगा।

वरुण नदी के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर (43 किमी)

वरुण नदी के समानांतर बनने वाला यह कॉरिडोर उत्तर और पूर्व वाराणसी के क्षेत्रों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

लंबाई व चौड़ाई: यह कॉरिडोर 43 किलोमीटर लंबा और 6/4 लेन का होगा।

अनुमानित लागत: इस परियोजना पर करीब 10,998 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।

कनेक्टिविटी: यह प्रोजेक्ट NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से सीधे जोड़ेगा।

अंशात्मक बुनियादी ढांचा: इस मुख्य कॉरिडोर के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण फ्लाईओवरों, लूप, रैंप और दोनों तरफ सुगम सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी बड़ी रफ्तार

धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी में हर साल लगभग 15 करोड़ (150 मिलियन) से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती देखने आते हैं। इस भारी आवक के कारण शहर के पारंपरिक मार्ग पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। इन दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से NH-19 (प्रयागराज-वाराणसी), BHU-रामनगर रोड और NH-35 (वाराणसी-मिर्जापुर) पर ट्रैफिक का लोड न्यूनतम रह जाएगा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों दोनों का कीमती समय बचेगा।

पर्यटन और स्थानीय

राम मंदिर के सीईओ बनने की होड़, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन, रिटायर्ड अफसरों में सबसे ज्यादा उत्साह

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद देशभर से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के महज 24 घंटे के भीतर ही इस पद के लिए 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है।

राम मंदिर ट्रस्ट ने नए ष्टश्वह्व के चयन के लिए तीन सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होते ही समिति के आधिकारिक ई-मेल पर बड़ी संख्या में आवेदन आने शुरू हो गए। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि तब तक आवेदनों की संख्या कई हजार तक पहुंच सकती है। उम्मीद से कहीं अधिक आवेदन मिलने के कारण सर्च कमेटी के सामने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की चुनौती है। इसके लिए समिति आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्रता की समीक्षा हेतु एक सचिव नियुक्त करेगी। सर्च कमेटी की 19 जुलाई को अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें प्राप्त आवेदनों की समीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा। प्रारंभिक छंटनी के बाद योग्य उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार (पर्सनल इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा।

5 फ्लोर की बिल्डिंग, 48 कमरे, 100 से ज्यादा लोग... मौत के मुंह से खींच लाई नोएडा फायर टीम

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेस-3 क्षेत्र स्थित सेक्टर-66 के मामूरा इलाके में बुधवार दोपहर एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 26 वर्षीय महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की तत्परता से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह ग्राउंड फ्लोर पर चार्जिंग में लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में स्पार्किंग को माना जा रहा है। पुलिस ने मामले में बिल्डिंग के मालिक और लीज धारक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी, वह जी+4 (ग्राउंड प्लस चार मंजिल) की बिल्डिंग थी, जिसमें करीब 50 परिवार रहते थे। प्रत्येक फ्लोर पर 2BHK के 6 फ्लैट (12 कमरे) थे। इस तरह बिल्डिंग में कुल 26 फ्लैट थे (48 कमरे) थे। ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पार्किंग में चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक स्पार्किंग हुई। इसके बाद आग पास में खड़े पेट्रोल वाहनों तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरी पार्किंग को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में धुआं और आग ऊपरी मंजिलों तक फैल गई, जिससे पूरी इमारत में अफरा-तफरी मच गई।

100 से अधिक लोगों का रेस्क्यू, 2 की गई जान

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया। मामूरा की संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने सामने स्थित इमारत में सीढ़ियां लगाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। इस दौरान करीब 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आग में गंभीर रूप से झुलसे 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

लोगों को कैसे किया गया रेस्क्यू?

बता दें कि जिस गली में ये बिल्डिंग थी, वहां का रास्ता काफी संकरा था। ऐसे में फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए लोगों का रेस्क्यू करना काफी चुनौतीपूर्ण था। फायर की एक टीम तुरंत बगल वाले घर के छत पर पहुंची और सीढ़ी लगाकर हादसे वाली बिल्डिंग की छत पर गई। चूंकि आग लगने की डर की वजह से काफी लोग छत पर आ गए थे, फिर धीरे-धीरे फायर टीम ने सभी को सीढ़ी की मदद से नीचे उतारा। वहीं बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर फंसे लोगों को एक अन्य फायर टीम ने रेस्क्यू किया।

CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अग्निकांड का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और राहत कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के आदेश भी जारी किए। साथ ही प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बिल्डिंग मालिक और लीज धारक हिरासत में, मुकदमा दर्ज

जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि हादसे के बाद थाना फेस-3 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भवन मालिक और लीज धारक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इमारत में फायर सेफ्टी से जुड़े सभी मानकों का पालन किया गया था या नहीं। यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संकरी गलियों ने बढ़ाई राहत कार्य की चुनौती

मामूरा क्षेत्र की घनी आबादी और संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को राहत एवं बचाव अभियान चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से शुरुआती समय में आग पर काबू पाने में अतिरिक्त प्रयास करने पड़े। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया और बड़ा हादसा टाल दिया।

फायर सेफ्टी व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक घटना के बाद एक बार फिर बहुमंजिला रिहायशी इमारतों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, इमरजेंसी एग्जिट और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

अब 90 सीटर विमान के लिए तैयार होगा हवाई अड्डा, 2120 किसानों से लेंगे जमीन

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। मुरादाबाद एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 163 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। छह गांवों के 2120 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। एयरपोर्ट विस्तार पर 3.35 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। हवाई अड्डे का विस्तार होने पर मुरादाबाद से बड़ी फ्लाइटें (70 से 90 सीटर) उड़ान भर सकेंगी।

शासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा है। वर्ष 2014 में मूंढापाड़े की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनी थी। इसके लिए प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू साइन हुआ। हवाई पट्टी को विकसित कर 52 हेक्टेयर भूमि पर हवाई अड्डे का निर्माण कराया गया। इस पर करीब 28.93 करोड़ खर्च किए गए। तमाम अड़चनों के बाद रक्षा मंत्रलाय, गृह मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से एनओसी मिलने पर 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। 10 अगस्त 2024 को पहली बार मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 सीटर जहाज को रवाना किया गया था। फिलहाल यहां से हवाई सेवा बंद है। इसके पीछे 19 सीटर जहाजों की कमी बताई गई। वहीं रनवे छोटा होने का कारण यहां से बड़ी फ्लाइट नहीं शुरू की जा सकती है। ऐसे में रनवे को बड़ा करने की जरूरत है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने हवाई अड्डे का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

163 हेक्टेयर भूमि पर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में छह गांवों की भूमि आएगी। प्रशासन भदासना, टहानायक, हरसैनपुर, सिरसखेड़ा, मूंढापांडे और नियामतपुर इकटोरिया गांव के 2012 किसानों की भूमि लेगा।

17 नवंबर 2024 से बंद है हवाई सेवा

मुरादाबाद हवाई अड्डे से हवाई सेवा 17 नवंबर 2024 से बंद है। मुरादाबाद-लखनऊ के बीच ये सेवा महज 45 दिनों तक ही बहाल रही थी। इस दौरान 1500 यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी।

अभी 30 मीटर चौड़ा और 2112 मीटर लंबा है रनवे

मुरादाबाद हवाई अड्डा करीब 1250 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका रनवे 30 मीटर चौड़ा है। जबकि इसकी लंबाई 2112 मीटर है। इस रनवे पर छोटी फ्लाइट ही उड़ सकती है। विस्तार होने पर रनवे की चौड़ाई 45 मीटर कर दी जाएगी। जबकि लंबाई 2600 मीटर तक हो सकती है।

70 से 90 सीटर विमान सेवा की हो सकती है शुरुआत

हवाई अड्डा विस्तार होने के बाद मुरादाबाद से 70 से 90 सीटर वाली फ्लाइट की शुरुआत हो सकती है। इससे मुरादाबाद के लोगों को लखनऊ आने जाने में सहूलियत होगी। साथ ही दूसरे शहरों के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू हो सकती है। हवाई सेवा शुरू करने के लिए हवाई अड्डे का विस्तार होना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन की ओर से तीन अरब 35 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

- ममता मालवीय, एडीएम वित्त एवं राजस्व

राहुल गांधी मानहानि मामले में बड़ा फैसला, वॉइस सैंपल मिलान की मांग खारिज

सुल्तानपुर। एडीजे-5 अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में वॉइस सैंपल के मिलान की मांग वाली रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले में पहले एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि बचाव पक्ष ने राहुल गांधी की वास्तविक आवाज का साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सीडी में रिकॉर्ड आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के जरिए मिलान कराने की मांग का विरोध किया था। निचली अदालत पहले ही इस मांग को अस्वीकार कर चुकी थी, जिसके खिलाफ भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से रिवीजन याचिका दायर की गई थी। बताया गया कि 30 जून को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार 15 जुलाई को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए रिवीजन याचिका भी खारिज कर दी। यह मामला वर्ष 2018 का है।

सीएमओ ने एचपीवी टीकाकरण का किया औचक निरीक्षण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए संचालित एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण व्यवस्था, लाभार्थियों के पंजीकरण और यू-विन पोर्टल पर डाटा अपलोड की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने बताया कि एचपीवी टीकाकरण सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन की एक खुराक दी जा रही है, जो वायरस के टाइप-16 एवं टाइप-18 से सुरक्षा प्रदान करती है। विशेषज्ञों के अनुसार 14 वर्ष की आयु में लगाया गया टीका लंबे समय तक प्रभावी सुरक्षा देता है। उन्होंने बताया कि भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार नए मामले सामने आते हैं और 42 हजार से अधिक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क एवं सुरक्षित है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों की किशोरियों तक समान रूप से इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है। जिला महिला चिकित्सालय में प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी, लेकिन 15 वर्ष पूर्ण न हुई किशोरियों को अभिभावक की सहमति के साथ निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। लाभार्थियों को आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने जिला महिला चिकित्सालय को निर्देश दिए कि एएनएम द्वारा 14 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी सभी किशोरियों की सूची तैयार कर उनके अभिभावकों से संपर्क किया जाए और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही लगाए गए सभी टीकों का विवरण यू-विन पोर्टल पर समय से अपलोड करते हुए एचपीवी कार्ड भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि जनपद में यू-विन पोर्टल पर पंजीकृत सभी बच्चों और माताओं का रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। एचपीवी टीकाकरण जनपद के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जिला महिला चिकित्सालय में प्रत्येक कार्यदिवस संचालित किया जा रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्लॉक दिवस में नहीं पहुंचते अधिकारी

कुड़वार/सुल्तानपुर। माह के तीसरे बुधवार को जन समस्याओं के लिए आयोजित होने वाला ब्लॉक दिवस महज दिखावा बनकर रह गया है। ब्लॉक दिवस में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने न आने से फरियादियों का ब्लॉक दिवस से मोह भंग हो गया है।

बुधवार को स्थानीय विकास खंड मुख्यालय पर बीडीओ विवेक कटियार की अध्यक्षता में ब्लॉक दिवस का आयोजन हुआ। ब्लॉक दिवस में केवल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले फरियादियों की ही मौजूदगी दिखी। विकास विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए ब्लॉक दिवस में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, सिंचाई, विपणन, बाल विकास विभाग को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन ब्लॉक दिवस में केवल विकास विभाग के सचिव, एडीओ, बाल विकास पुष्टाहार व सिंचाई विभाग के कर्मचारी ही मौजूद रहे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी : दो आरोपियों को रिमांड पर लेकर जेल से निकली पुलिस, पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस बुधवार सुबह जिला जेल से आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की कस्टडी रिमांड के लिए लेकर निकल गई। सुबह करीब 8:10 बजे पुलिस टीम जिला जेल पहुंची। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस लाइन परिसर में दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर उनकी निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जाएगी। इस दौरान पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा।

अब तक नगदी, आभूषण तथा दो चार पहिया वाहन बरामद

पुलिस अब तक चार आरोपियों से कस्टडी रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है और उनकी निशानदेही पर नगदी, आभूषण तथा दो चार पहिया वाहन बरामद कर चुकी है। रमाशंकर मिश्रा के पास से पहले करीब सात लाख रुपये बरामद हुए थे, जबकि गणना प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव के पास से अब तक कोई नकदी बरामद नहीं हुई है।

पुलिस ने सात दिन की मांगी थी रिमांड

बताते चलें कि अदालत ने आरोपी रमाशंकर मिश्रा और गढ़ना प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की है। विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से सात दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 14 घंटे की रिमांड स्वीकृत की। अब पुलिस दोनों आरोपियों को कस्टडी में ले चुकी है, इनसे पूछताछ करेगी।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और काशी में एलिवेटेड कॉरिडोर... कैबिनेट ने मेगा प्लान को दी मंजूरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने और पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि ये प्रोजेक्ट्स शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेंगे और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेंगे।

पहले प्रोजेक्ट के तहत, वरुणा नदी के किनारे 6-लेन और 4-लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। लगभग 43 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर नमो घाट से शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹10,998 करोड़ है और इसे चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को जोड़कर, यह कॉरिडोर शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।

हर साल आते हैं 15 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वाराणसी में हर साल लगभग 15 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है ताकि यात्रा सुरक्षित और आसान हो सके। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काशी में गंगा नदी के किनारे एक और 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है।

प्रोजेक्ट पर ₹14,448 करोड़ होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 46 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर ₹14,448 करोड़ का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर के बनने से श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान हो जाएगी और शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा। केंद्रीय मंत्री अनुसार, ये दोनों प्रोजेक्ट्स वाराणसी के समग्र शहरी विकास, पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे, साथ ही शहर की कनेक्टिविटी को भी काफी मजबूत करेंगे।

रेलवे में आठ नए सुधारों की घोषणा

इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेलवे में आठ नए सुधारों की घोषणा की। इनका मकसद रेलवे के कामकाज को बेहतर बनाना और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और फायदे पहुंचाना है। इन सुधारों के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा कि इन उपायों से व्यापारियों और यात्रियों, दोनों को कई फायदे होंगे। माल ढुलाई की लागत कम करने, सप्लाई चेन को बेहतर बनाने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां शुरू की गई हैं।

डंगोआपोसी और राजखरसवां के बीच रेलवे लाइन को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट कैबिनेट ने डंगोआपोसी और राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी, जिसकी लागत ₹1,365 करोड़ होगी। कैबिनेट ने पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन को दोगुना करने की मंजूरी दी। 74 किलोमीटर लंबे इस रूट पर ₹2,542 करोड़ का खर्च आएगा। इससे 25 लाख (2.5 मिलियन) 'पर्सन-डे' (काम के दिन) का रोजगार पैदा होगा और कोयला, लौह अयस्क और कोकिंग कोल के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी।

यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी। यूरिया की मांग हर साल 5% बढ़ रही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेचुरल गैस पर आधारित यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत 7 से 8 नए प्लांट लगाए जाएंगे। नई स्कीम से हर प्लांट पर ₹250 करोड़ की बचत होगी और यूरिया के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी।

MPMS स्कीम को मंजूरी, 60000 लोगों को मिलेगा रोजगार

कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दी। यह स्कीम पांच साल के लिए है और इसमें इंसेंटिव (प्रोत्साहन) दिए जाएंगे। भारतीय ब्रांड्स के डिजाइन और R&D के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन 'मेड इन इंडिया' हैं। इस स्कीम से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़े सेक्टर में 60,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा।

'सेमीकॉन 2 ।0' को मंजूरी

कैबिनेट ने ₹1,27,500 करोड़ की लागत से 'सेमीकॉन 2.0' को मंजूरी दी। इसका मकसद भारत को चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। 'सेमीकॉन 1।0' के तहत 12 प्लांट को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से तीन में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ₹4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। ₹2 लाख करोड़ के प्रोडक्शन और ₹1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट की उम्मीद है।

विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया युवाओं का सम्मान, बोले-

स्किल्ड युवा ही विकसित भारत और एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की आधारशिला

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। आज देश और दुनिया में काम की कमी नहीं है, बल्कि कुशल युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक युवा कार्यबल वाला राज्य है और सरकार इस जनशक्ति को डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में विकसित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अब नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि स्टार्टअप और उद्यमिता के माध्यम से रोजगार देने वाले बन रहे हैं, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर

रोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की पत्रिका 'कौशलम' का विमोचन किया तथा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनेस्को ने वर्ष 2026 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम 'स्किल फॉर शेयर्ड फ्यूचर' (साझा भविष्य के लिए कौशल) निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि साझा भविष्य तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिलें और अवसर तभी उपलब्ध होते हैं जब सरकार की सोच समावेशी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में पहली बार देश में कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके बाद राज्यों में भी कौशल विकास को नई दिशा मिली।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी और युवाओं को आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं मिल पाता था। रोजगार के अवसर सीमित थे और सरकारी नौकरियों में भेदभाव की शिकायतें आम थीं। लेकिन वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में व्यापक बदलाव हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन, औद्योगिक निवेश और कौशल विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इसका उदाहरण है, जहां आईटीआई, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिल रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव और सिफारिश के नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। वहीं प्रदेश की 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से सवा तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, मेरठ का खेल सामग्री उद्योग, लखनऊ की चिकनकारी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और वाराणसी का साड़ी उद्योग लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने पारंपरिक ट्रेडों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और थ्री-डी प्रिंटिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के साथ-साथ महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया और बहराइच जैसे जिलों में भी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। युवाओं को रोजगार मेले, कैंपस प्लेसमेंट और करियर काउंसिलिंग के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जा रहा है।मुख्यमंत्री ने युवाओं से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बरेली की युवती राजरानी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह प्रतिमाह 27 हजार रुपये कमाकर अपनी मां का इलाज करा रही हैं और परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार राजरानी की मां के इलाज में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रम एवं सेवायोजन, एमएसएमई तथा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करेगी। इन केंद्रों में युवाओं की रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। विदेशों में रोजगार के इच्छुक युवाओं को संबंधित देशों की भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

बीबीएयू में यूजी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 30 जुलाई तक करें ऑनलाइन पंजीकरण

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (यूजी) एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सीयूईटी-यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध यूजी प्रवेश प्रॉस्पेक्टस 2026-27 तथा छात्रावास (हॉस्टल) मैनुअल का सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 65 हजार रुपये जुर्माना

लखनऊ। लखनऊ पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की संयुक्त पैरवी से नाबालिग किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने दोनों दोषियों पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।यह मामला वर्ष 2022 में बंथरा थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 343/2022 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366ए, 376डी(बी) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त रामेश्वर रावत और अनुज रावत, निवासी खाण्डेदेव, थाना बंथरा, को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लखनऊ में 17 वर्षीय घरेलू सहायिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के सआदतगंज थाना क्षेत्र के रामनगर सी-ब्लॉक स्थित एक मकान में 17 वर्षीय घरेलू सहायिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवती का शव मकान के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार मकान स्वामी ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने के बजाय युवती को फंदे से उतारकर बरामदे में लिटा दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई 2026 की रात लगभग 9 बजे थाना सआदतगंज क्षेत्र के रामनगर सी-ब्लॉक स्थित एक मकान में एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना सआदतगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।जांच में मृतका की पहचान रजनी (17 वर्ष), पुत्री रामशरण, निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना सदरपुर, जनपद सीतापुर के रूप में हुई। वह अविवाहित थी और पिछले लगभग तीन वर्षों से रामनगर स्थित मकान में घरेलू कार्य, जैसे झाड़ू-पोछा आदि, करती थी।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के समय युवती ने मकान के बाथरूम में फांसी लगा ली थी। पुलिस के अनुसार मकान स्वामी रामगोपाल वर्मा ने पुलिस को तत्काल सूचना दिए बिना पहले युवती को फंदे से उतारकर मकान के बरामदे में लिटा दिया। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रामगोपाल वर्मा की मोहन रोड स्थित फतेहगंज चौराहे पर एक आभूषण की दुकान भी है।

उत्तर प्रदेश आज टॉप-3 अर्थव्यवस्था, कानून का राज और सुशासन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि' : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कानून-व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। जो प्रदेश कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, वह आज देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट नीति और दृढ़ नीयत के साथ काम करते हुए कानून का राज स्थापित किया है, जिसके कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी है तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी भी तीन गुना हुई है।मुख्यमंत्री 'पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश' कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं। आज प्रदेश निवेश, रोजगार, उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद के रूप में उन्होंने प्रदेश की मूलभूत समस्याओं को करीब से देखा था। उस समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी, माफिया का प्रभाव था, बिजली संकट, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं आम थीं। वर्ष 2017 के बाद सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कर अपराध, माफिया और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा, कर्फ्यू और माफिया मुक्त राज्य के रूप में नई पहचान बना चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में निवेश का माहौल नहीं था और युवा अपनी पहचान छिपाने को मजबूर थे। आज सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका है और इनके माध्यम से 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। जल्द ही 7.5 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का भी ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों को सिंचाई, बिजली, बीज और उर्वरक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सहित कई लंबित सिंचाई योजनाएं पूरी कर लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। किसानों को निजी नलकूपों पर निःशुल्क बिजली दी जा रही है और गन्ना किसानों को नौ वर्षों में 3.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जिनसे सवा तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सरकार इन इकाइयों को तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रखता है। प्रदेश में 17 हवाई अड्डे संचालित हैं, जिनमें पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन से प्रदेश की वैश्विक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। साथ ही मेट्रो, रैपिड रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसी परियोजनाओं ने परिवहन व्यवस्था को नई दिशा दी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। अब डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। प्रदेश के लगभग 16 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबों को आवास, शौचालय, पेयजल, आयुष्मान भारत योजना और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है।

एसबीआई एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुडम्बा पुलिस ने एसबीआई एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी नकदी चोरी करने का प्रयास करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध 12 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त पेचकस, प्लास और आरी ब्लेड बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई 2026 को राम धर्म कांटा के पास स्थित एसबीआई एटीएम में अज्ञात व्यक्ति ने मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी धनराशि चोरी करने का प्रयास किया था। घटना के संबंध में गुडम्बा थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।विवेचना के दौरान

बैंक के कंट्रोल रूम से प्राप्त लगभग पांच सेकेंड की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। फुटेज में एक संदिग्ध युवक सफेद टी-शर्ट और गले में सफेद गमछा पहने एटीएम कक्ष में प्रवेश करता दिखाई दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर की सूचना और लगातार की गई पतारसी के आधार पर आरोपी मो. निहाल को सेक्टर-जे पुलिस चौकी के आगे से गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उसने पेचकस, प्लास और आरी ब्लेड की मदद से एटीएम मशीन तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी करने का प्रयास किया था। हालांकि मशीन से तेज आवाज आने पर पकड़े जाने के डर से वह मौके से फरार हो गया था।

जन्नत बार फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा बरामद

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने जन्नत बार एंड रेस्टोरेंट में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध .315 बोर का देशी तमंचा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं।पुलिस के अनुसार, 12 और 13 जून 2026 की रात कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए जन्नत बार एंड रेस्टोरेंट पहुंचे थे। पार्टी के दौरान नशे की हालत में कुछ युवक बार-बार डीजे कंसोल पर चढ़कर डांस करने लगे। बार के बाउंसरों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद और हाथापाई हो गई। आरोप है कि इसी दौरान सौरभ सिंह अपनी स्कॉर्पियो से अवैध तमंचा निकाल लाया और बार स्टाफ पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर मौके से फरार हो गया।

लखनऊ में 18 माह की बच्ची के अपहरण का खुलासा : पांच आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी के चौक थाना क्षेत्र से 18 माह की मासूम बच्ची के अपहरण के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्ची का अपहरण उसे बेचने की नीयत से किया गया था। हालांकि जिस व्यक्ति के लिए बच्ची को ले जाया जा रहा था, उसने उम्र अधिक होने का हवाला देकर उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी बच्ची को आलमबाग क्षेत्र की मछली मंडी में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता को सौंप दिया है, जबकि पूरे गिरोह के नेटवर्क की जांच जारी है।पुलिस के अनुसार 13 जुलाई 2026 को वादी ने थाना चौक में सूचना दी कि रात करीब 2:30 बजे नेशनल

मेडिकल के बरामदे के पास से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही थाना चौक में मुकदमा संख्या 149/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विशेष पुलिस टीम गठित की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस की सक्रियता और लगातार दबिश के कारण आरोपी उसी दिन बच्ची को आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित मछली मंडी में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया।इसके बाद आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। जांच के दौरान करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सर्विलांस टीम की तकनीकी सहायता और लगातार की गई छानबीन के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हुई। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे बाजारखाला थाना क्षेत्र के मालवीय नगर मोड़ के पास पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ कश्यप, रोहित पासी उर्फ जादू, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद इरशाद शाह और श्यामजी यादव के रूप में हुई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है।पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। आरोपियों ने बताया कि हरदोई निवासी शेर सिंह को एक बच्चे की आवश्यकता थी। उसने इस संबंध में अपने करीबी श्यामजी यादव से बात की। इसके बाद श्यामजी यादव ने मोहम्मद सुल्तान के माध्यम से बच्चा

इटावा के पूर्व विधायक राम लखन धोबी के पुत्र ऋषि दिवाकर समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में इटावा के लखना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राम लखन धोबी के पुत्र ऋषि दिवाकर ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा।इस अवसर पर अजय राय ने ऋषि दिवाकर और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम के नाम पर राजनीति कर सत्ता हासिल की, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों में

चंदा, जमीन खरीद और चढ़ावे को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस जनता के सहयोग से उन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी।कार्यक्रम में ऋषि दिवाकर के साथ लखना नगर पंचायत के सभासद बंटी उर्फ फिरोज, जानू तिवारी, पंकज यादव, अशोक दोहरे, मोहम्मद तसलीम, अवनीश त्रिपाठी, विवेक तिवारी, परवार वारसी, रामबाबू त्रिपाठी, शिवरतन दिवाकर, साधना सविता, संजू चौहान, पलक, वंशिका चौहान, सत्य प्रकाश शुक्ला, संजीव त्रिपाठी, हरेन्द्र त्रिपाठी सहित दर्जनों समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।कार्यक्रम में इटावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, बांदा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न दुबे सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सीसीटीवी की पांच सेकेंड की फुटेज से खुला एटीएम तोड़कर चोरी के प्रयास का राज, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। गुडम्बा थाना पुलिस ने एसबीआई एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी करने के प्रयास का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 12 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस तथा घटना में इस्तेमाल किए गए पेचकस, प्लास और आरी ब्लेड बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई को राम धर्म कांटा के पास स्थित एसबीआई एटीएम में अज्ञात व्यक्ति ने मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी धनराशि चोरी करने का प्रयास किया था। घटना के संबंध में गुडम्बा थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।जांच के दौरान बैंक के कंट्रोल रूम से मिली मात्र पांच सेकेंड की सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। फुटेज में सफेद टी-शर्ट और गले में सफेद गमछा पहने एक संदिग्ध युवक एटीएम कक्ष में प्रवेश करता दिखाई दिया।

लखनऊ पुलिस ने हाईटेक फ्यूल चोरी और मिलावट करने वाले संगठित गिरोह का किया भंडाफोड़

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 'ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड' के तहत पेट्रोल-डीजल की चोरी, अवैध मिलावट और कालाबाजारी में संलिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, अपमिश्रित ईंधन, साल्वेंट तथा चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह आधुनिक तकनीक, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, हाई सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दुरुपयोग कर सुनियोजित तरीके से ईंधन चोरी और मिलावट का कारोबार संचालित कर रहा था।पुलिस के अनुसार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों की जांच के दौरान यह संदेह हुआ कि वाहनों में आने वाली तकनीकी समस्याओं के पीछे पेट्रोल और डीजल में अवैध मिलावट तथा ईंधन चोरी का नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। इसी के बाद क्राइम ब्रांच ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड' शुरू किया।विश्वसनीय सूचना पर थाना मलिहाबाद क्षेत्र के सन्यासी बाग फ्लाईओवर के पास छापेमारी की गई, जहां एक फ्यूल टैंकर और अन्य वाहन से 7,750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, लगभग 1,150 लीटर अपमिश्रित पेट्रोल, 3,200 लीटर साल्वेंट तथा चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। आबकारी विभाग की संयुक्त जांच में ईंधन की चोरी और मिलावट की पुष्टि हुई।जांच में सामने आया कि आरोपी टैंकर में लगे जीपीएस सिस्टम का पावर स्रोत अस्थायी रूप से हटाकर उसे बंद कर देते थे, जिससे कंट्रोल रूम में वाहन एक ही स्थान पर खड़ा दिखाई देता था। इस दौरान टैंकर को चोरी और मिलावट के ठिकानों तक ले जाकर ईंधन निकाल लिया जाता था। बाद में उसी स्थान पर लौटकर जीपीएस दोबारा चालू कर दिया जाता था, जिससे पूरी गतिविधि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती थी।पुलिस ने यह भी पाया कि आरोपी लगभग 70 हजार रुपये कीमत वाले सेंसर आधारित हाई सिक्योरिटी लॉक को विशेष रूप से तैयार की गई मास्टर-की और धातु के पतले तार की मदद से निष्क्रिय कर देते थे। इससे लॉक खुलने का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता था और न ही संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के पास ओटीपी आधारित सूचना पहुंचती थी।पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह तापमान के अनुसार पेट्रोल और डीजल के फैलने-सिकुड़ने के वैज्ञानिक सिद्धांत का लाभ उठाकर चोरी की मात्रा को छिपाता था। चोरी किया गया ईंधन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेचकर अवैध मुनाफा कमाया जाता था।

अमेरिका-ईरान टकराव और विश्व शांति की नई चुनौती

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद बड़ी कठिनाई से बना संघर्ष विराम अपनी निर्धारित अवधि पूरी करने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ताजा हमलों और उसके जवाब में अमेरिका की भीषण बमबारी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को युद्ध की आशंकाओं के बीच खड़ा कर दिया है। यह केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। जिस समय विश्व को महामारी, आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना चाहिए, उस समय महाशक्तियों का युद्धोन्माद पूरी मानवता को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न विवाद ने इस संघर्ष को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो केवल तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटेंगी और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। युद्ध की आग कभी सीमाओं में नहीं रहती, उसकी तपिश अंततः पूरी दुनिया को झुलसाती है। राजनीति

इस संघर्ष का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें निर्दोष नागरिकों, नाविकों और आम जनजीवन को सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के घटनाक्रम में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने और भारत के सहयोग से विकसित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह परियोजना को नुकसान पहुंचने से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक विश्वास-तीनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका स्वयं को लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था का संरक्षक बताता है, लेकिन उसकी विदेश नीति लंबे समय से प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित रही है। किसी भी राष्ट्र को झुकाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हमले और राजनीतिक दबाव स्थायी समाधान नहीं हो सकते। महाशक्ति होने का अर्थ केवल सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि संयम, दूरदृष्टि और विश्व समुदाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि शक्ति विवेक से संचालित न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।

दूसरी ओर ईरान को भी यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को अपने रणनीतिक हितों के लिए बंधक बनाना न तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और न ही वैश्विक विश्वास के अनुकूल। किसी भी देश की सुरक्षा तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के साथ सहयोग, विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण निर्मित न करे। भय और प्रतिशोध पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था अंततः स्वयं को ही असुरक्षित बना देती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने इस पूरे संकट को और अधिक अनिश्चित बनाया है। एक ओर वे कठोर सैन्य कार्रवाई करते हैं, दूसरी ओर वार्ता और समझौते की बातें करते हैं। इस प्रकार के विरोधाभासी संदेश न केवल कूटनीतिक विश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अस्थिरता पैदा करते हैं। महाशक्तियों के नेताओं के प्रत्येक वक्तव्य का प्रभाव केवल उनके देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था, निवेश, ऊर्जा बाजार और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए नेतृत्व में धैर्य, स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

इतिहास गवाह है कि युद्धों ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया तक, हर युद्ध ने नई समस्याएं ही पैदा की हैं। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लेकिन अंततः समाधान फिर बातचीत की मेज पर ही खोजे गए। यदि अंत में संवाद ही करना है, तो शुरुआत भी संवाद से ही क्यों नहीं हो सकती? यही प्रश्न आज पूरी मानवता के सामने खड़ा है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी की भूमि ने यह सिखाया कि वास्तविक विजय शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि शत्रुता को समाप्त करने में है। भारत की विदेश नीति भी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'विश्वबंधुत्व' के आदर्शों पर आधारित रही है। भारत ने हमेशा संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही कारण है कि भारत आज विश्वसनीय मध्यस्थ, संतुलित शक्ति और जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में सम्मान प्राप्त कर रहा है। वर्तमान संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के भारत के 5एफ विज़न को बुनता टेक्स 2026

वस्त्र उद्योग सिर्फ हमारी विरासत की झलक नहीं है, यह भारत के मैक्रो-इकोनॉमिक ढांचे की एक मज़बूत नींव भी है।

पबित्रा मार्गेरिटा

कश्मीरी पश्मीना की नरम गर्माहट से लेकर असम के मूंगा सिल्क की शानदार चमक तक, राजस्थानी बांधनी के जीवंत ज्यामितीय पैटर्न से लेकर कांजीवरम सिल्क की सदाबहार और बेहतरीन बनावट तक, भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता धागों से बुना एक जीता-जागता नक्शा है। आज, सभ्यता की यह बेमिसाल तस्वीर एक ही छत के नीचे एक साथ नज़र आ रही है। नई दिल्ली के प्रसिद्ध भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई तक भारत टेक्स 2026 का आयोजन, हमारे देश की खूबसूरत विविधता को एक ही मंच पर ला रहा है।

वस्त्र उद्योग सिर्फ हमारी विरासत की झलक नहीं है, यह भारत के मैक्रो-इकोनॉमिक ढांचे की एक मज़बूत नींव भी है। यह क्षेत्र लगातार विकास और समानता का एक बहुत बड़ा इंजन बना हुआ है, जो जीडीपी में 2.3त्न, औद्योगिक उत्पादन में 13त्न और निर्यात में 8.6त्न का योगदान देता है। कृषि के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला यह क्षेत्र 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की आजीविका का साधन है, जो ग्रामीण समुदायों को मज़बूत बनाता है और देश भर में लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है।

आर्थिक शक्ति के इस केंद्र को सही मायने में समझने के लिए भारत टेक्स का अनुभव करना बेहद ज़रूरी है। यह वैश्विक स्तर पर प्रमुख भारतीय वस्त्रों का व्यापार मेला है, जिसे पूरी दुनिया के सामने हमारे निर्माण और रचनात्मकता की क्षमता का दबदबा दिखाने के लिए तैयार किया गया है। यह एक ऐसा व्यापक बाज़ार है, जहाँ घरेलू निर्माणकर्ता, राज्यों के पवेलियन, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक और वैश्विक खरीदार एक ही छत के नीचे होते हैं। इससे बड़े पैमाने पर सोर्सिंग, कॉर्पोरेट जुड़ाव और ब्रांड को प्रदर्शित करने के अवसर भी मिलते हैं।

इस शानदार पहल के सफ़र पर नज़र डालें तो मुझे भारत टेक्स के पिछले दो आयोजनों से बेहद गर्व की अनुभूति का स्मरण होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स के पिछले संस्करण के दौरान संपूर्ण वस्त्र समुदाय को संबोधित किया था, तो उन्होंने बेहद खूबसूरती से कहा था कि हमने जो बीज बोया था, वह अब तेज़ी से बरगद के पेड़ का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह भव्य आयोजन न केवल हमारी समृद्ध परंपराओं का जश्न मनाता है, बल्कि एक विकसित भारत की अपार संभावनाओं को भी उजागर करता है। पहले दो आयोजनों की ज़बरदस्त सफलता ने एक मज़बूत नींव रखी, बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया और सहयोग की दिशा में भी तेज़ी देखने को मिली। भारत टेक्स 2025 के दौरान मेरे व्यक्तिगत अनुभव ने भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक नज़रिया हासिल किया, जहाँ मैंने सरकार से सरकार और व्यापार से सरकार के बीच गहन बातचीत को ठोस नतीजों में बदलते देखा और इसी के चलते भारत की कार्य क्षमता में बढ़ते वैश्विक भरोसे की झलक भी दिखी। यह तीसरा आयोजन उस रफ्तार को और आगे ले जाता है और शुरुआती संभावनाओं को पूरी तरह से औद्योगिक प्रभाव में बदलता है।

इस साल के कार्यक्रम का बहुत बड़ा पैमाना एक सोची-समझी औद्योगिक रणनीति को दर्शाता है। भारत मंडपम में खास प्रदर्शनी हॉलों में फैली यह प्रदर्शनी भारत की पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला को दिखाती है, जिसमें फाइबर, यार्न, फैब्रिक, कपड़े और फैशन, होम टेक्सटाइल, तकनीकी वस्त्र और सहायक उद्योग शामिल हैं। इसमें 1,600 से ज़्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं, जो स्थानीय उत्पादन की ताकत को सीधे वैश्विक मंच पर पेश करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी के क्रांतिकारी 5एफ विज़न- फार्म (खेत) से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन (विदेश) तक के सफर को दर्शाता है। पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही औद्योगिक श्रृंखला में जोड़कर, यह कार्यक्रम विनिर्माण के हर चरण को देश में ही संभालने की भारत की आत्मनिर्भर क्षमता को दिखाता है।

इस पहल को दुनिया भर से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस संस्करण में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल समेत 14 देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल हैं, साथ ही, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ का भी मज़बूत संस्थागत प्रतिनिधित्व है। कई देशों के मंत्री-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि दीर्घकालीन साझेदारी की संभावना तलाशने के लिए इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि चार दिनों में 110 से ज़्यादा पंजीकृत देशों से 7,000 से ज़्यादा खरीददार और 1.3 लाख व्यापारिक आगंतुक आएंगे, जो वहां दिखाए जा रहे 20,000 से ज़्यादा वस्त्र उत्पादों को देखेंगे। इस व्यावसायिक गतिविधि में 3,500 से ज़्यादा खास तौर पर आयोजित बिज़नेस टू बिज़नेस बैठकें होंगी। इसके अलावा, राज्य निवेशक संपर्क सत्र भी होंगे, जो अलग-अलग भारतीय राज्यों को अपने खास औद्योगिक ढांचे को पेश करने का मंच प्रदान करेंगे।

उद्योगों को आगे बढ़ाने हेतु वास्तविक नेतृत्व के लिए ज्ञान और भविष्य की योजना के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। भारत टेक्स 2026 इस ज़िम्मेदारी को वैश्विक वस्त्र वार्ता के ज़रिए निभाता है, जिसमें पैनल चर्चा, राउंडटेबल, मास्टरक्लास, राज्य सत्र, अवॉर्ड्स पिच फेस्ट और कार्यशाला जैसे 100 से ज़्यादा खास सत्र शामिल हैं। 370 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीएक्सओ, पॉलिसी निर्माता और अन्वेषकों की अगुवाई में होने वाले ये खास सत्र व्यापार और निवेश को बढ़ाने, तकनीक और नवाचारों को आगे बढ़ाने और फैशन तथा क्राफ्ट को बेहतर बनाने पर फोकस करेंगे। इस कार्यक्रम में व्यापार, निवेशक, तकनीक और संस्थागत सहयोग से जुड़े कई रणनीतिक समझौतों और क्षेत्रों से जुड़ी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और उन्हें लॉन्च भी किया जाएगा।

इन चर्चाओं में वहनीयता और सर्कुलैरिटी जैसे अहम पहलुओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। पिछले कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि वैश्विक फैशन समुदाय तेज़ी से पर्यावरण के लिए फैशन के दृष्टिकोण को अपना रहा है और वहनीयता हमेशा से भारत की टेक्सटाइल विरासत का अहम हिस्सा रही है। भारत टेक्स का यह संस्करण वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को एक बड़े अवसर में बदलता है और यह दिखाता है कि कैसे नवाचारों की मदद से हमारी पारंपरिक तकनीकें और बेहतर हुई हैं और इस दौरान ये भी ख्याल रखा गया है कि इस प्रक्रिया में संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और बर्बादी कम हो, जिससे हमारे बुनकरों और कारीगरों को सीधा फायदा हो। हमारे वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में, मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर इन आधुनिकीकरण और वहनीय वृद्धि की पहलों को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मज़बूत आधुनिक तकनीक, बड़े पैमाने पर लागू होने वाले नीतिगत फ्रेमवर्क और मज़बूत मार्केट लिंकेज का सहारा मिले।

व्यंग्य

एक भी शहर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित नहीं

भारत के अंदर दो भारत की बात करें तो आर्थिक व सामाजिक आधार पर दो विभाजन के साथ साथ भौगोलिक विभाजन के आधार पर भी दो भारत दिखेंगे। यह विभाजन उत्तर और दक्षिण भारत का है। हर मामले में दोनों भौगोलिक इलाकों का अंतर साफ दिखाई देगा। उत्तर भारत या हिंदी पट्टी से बड़ी संख्या में लोग चेन्नई के शंकर नेत्रालय में इलाज के लिए जाते हैं। वहां से लौट कर हर व्यक्ति दक्षिण जाने वाली ट्रेनों की व्यवस्था, साफ सफाई का जिक्र करेगा और यह भी बताएगा कि अस्पताल कितना अच्छा है। दक्षिण के मंदिरों में जाकर लौटने वाले तो उनका गुणगान करते नहीं थकते हैं। खासतौर पर मंदिर की व्यवस्था और सफाई की। लेकिन सवाल है कि मंदिर या अस्पताल या ट्रेन की व्यवस्था उत्तर भारत में भी बेहतर क्यों नहीं हो सकती है? वैसी ही सफाई उत्तर भारत में भी क्यों नहीं होती? यह बुनियादी अंतर कई चीजों में दिखाई देता है।

अगर सिर्फ इस सदी के 25 साल की बात करें तो उत्तर और दक्षिण के दो बुनियादी रूप से अलग भारत की तस्वीर और साफ दिखेगी। इस सदी में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और आईटी क्रांति के इर्द गिर्द जैसा काम दक्षिण में हुआ है उसके मुकाबले उत्तर भारत में कुछ नहीं हुआ। दक्षिण में होड़ लगा कर बेंगलुरू और हैदराबाद ने काम किया। यह बहस छिड़ी कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाए। इस तरह की कोई होड़ उत्तर भारत के राज्यों में नहीं दिखी। एक तरफ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आईटी और आईटी आधारित सेवाओं की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे थे तो तमिलनाडु ने दूसरी औद्योगिक इकाइयों को प्रमोट किया। चेन्नई से चारों दिशाओं में सौ किलोमीटर के दायरे में देशी, विदेशी कंपनियों के अनगिनत प्लांट लगे हैं। उधर केरल ने अपने यहां शिक्षा व स्वास्थ्य की सबसे अच्छी व्यवस्था विकसित की।

दक्षिण में पिछली एक चौथाई सदी में कई शहर बस गए और कई नए शहर बसाए जा रहे हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार फोर्थ सिटी बसा रही है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के बाद अब रंगारेड्डी जिले में फ्यूचर सिटी के नाम से चौथा शहर बस रहा है। इसके लिए 50 हजार एकड़ जमीन लेकर शहर विकसित किया जा रहा है। इस फ्यूचर सिटी में एआई सिटी, हेल्थ सिटी, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्स हब अलग अलग बनाए जा रहे हैं। शहर का अपना मेट्रो और रैपिड रेल सिस्टम होगा। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है यानी पूरी तरह से नया शहर विकसित किया जा रहा है। इसे नेट जीरो की तर्ज पर बसाया जा रहा है यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। इस पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और बनने से पहले ही दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों ने वहां लाखों करोड़ के निवेश का समझौता कर लिया है।

इसी तरह आंध्र प्रदेश में नई राजधानी के तौर पर विजयवाड़ा को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नए शहर विकसित करने का अनुभव है। विजयवाड़ा के साथ साथ वे विशाखापत्तनम को भी नए सिरे से विकसित कर रहे हैं। बंदरगाह के साथ साथ विशाखापत्तनम अब डाटा सेंटर का हब बन रहा है। इसके मुकाबले उत्तर भारत में राज्यों की राजधानियों के आसपास सेटेलाइट शहर बनाने की घोषणाएं हो रही है, जिनका मकसद सिर्फ जमीन के दाम बढ़ाना है। जो नए शहर बसाए गए चाहे वह नोएडा हो या गुरुग्राम उनकी हालत धीरे धीरे नर्क से बदतर होती जा रही है। पानी निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। बिना किसी योजना के उनके विकास है। सोचें, सेटेलाइट शहर बसाने के लिए उत्कर भारत में पांच सौ और हजार करोड़ रुपए का बजट घोषित होता है। यह वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की योजना घोषित की थी। इसके तहत एक एक हजार करोड़ रुपए दिए जाने की खबर आई। इतनी रकम में एक या दो अच्छे फ्लाइओवर बन जाएं तो वह बड़ी बात होगी। तभी एक भी शहर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित नहीं हुआ है।

ब्लॉग

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन: कृषि मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) के माध्यम से पूरे देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आधुनिक कृषि मशीनों तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। कृषि मशीनीकरण में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उन राज्यों एवं क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां कृषि यंत्रों का उपयोग अपेक्षाकृत कम है। योजना के शुरू होने से अब तक 9,404.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से देशभर के किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा, 52.5 करोड़ रुपये की सहायता से 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,928 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इन प्रदर्शनों ने किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मशीनीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के पूरे चक्र में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, फसल संरक्षण, कटाई एवं कटाई के बाद के प्रबंधन जैसे सभी प्रमुख कार्य शामिल हैं। कृषि मशीनीकरण से मानव और पशु श्रम पर निर्भरता कम होती है, जिससे कृषि कार्य समय पर, अधिक दक्षता व सटीकता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत घटती है, श्रम उत्पादकता बढ़ती है, कृषि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आय और खेती की समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत केंद्र प्रायोजित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनों एवं उपकरणों का लाभ उन किसानों और क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इस योजना का विशेष ध्यान छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा ग्रामीण उद्यमियों पर है।

यह योजना कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना को बढ़ावा देती है। ये ऐसे केंद्र हैं, जहां कृषि मशीनें, औजार और उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। यह योजना उच्च-प्रौद्योगिकी और महंगे कृषि उपकरणों के लिए हब स्थापित करने तथा कृषि मशीनरी के वितरण में भी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत प्रदर्शन और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाती है। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर और कृषि शक्ति अपेक्षाकृत कम है। साथ ही, कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से सस्ती किराया सेवाएं उपलब्ध कराकर छोटे जोत आकार और अधिक लागत जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाता है। इसके अलावा, कृषि मशीनीकरण पर सब-मिशन के तहत कृषि मशीनरी के प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन को भी सहायता प्रदान की जाती है। इससे जुड़े हितधारकों के बीच इनका उपयोग बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं।

वर्ष 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि मशीनीकरण तथा मूल्य संवर्धन जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2017-18 में इस योजना का पुनर्गठन कर इसे आरकेवीवाई-रफ्तार (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण) के रूप में लागू किया गया, जिसमें फसल-पूर्व और फसलोपरांत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच बेहतर बनाकर, श्रम की आवश्यकता कम करके और खेती की उत्पादकता बढ़ाकर समावेशी तथा कुशल कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शन व फसल कटाई के बाद के कामों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना: आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच बढ़ाकर कृषि उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। साथ ही, कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करते हुए फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य संवर्धन तथा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करता है।

खेती-बाड़ी के यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक मदद: यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कृषि मशीन की लागत का 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, छोटे एवं सीमांत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ड्रोन सहित मशीनीकृत कृषि सेवाओं के उपयोग के लिए प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

किराये पर मशीनें देने के लिए 'फार्म मशीनरी बैंक' (एफएमबी) बनाना: यह योजना एसएचजी, एफपीओ और स्थानीय संस्थाओं को कृषि मशीनें खरीदने के लिए 80 से 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। सीएचसी की स्थापना के लिए 250 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर कुल लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एफएमबी की स्थापना के लिए 30 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

हाई-टेक और ज्यादा उत्पादकता वाले इक्विपमेंट हब बनाना: कार्यकुशलता बढ़ाने तथा महंगी और उन्नत कृषि मशीनों तक किसानों की पहुंच आसान बनाने के लिए फसल-विशिष्ट कार्यों हेतु उन्नत एवं उच्च क्षमता वाली कृषि मशीनरी से सुसज्जित केंद्रों की स्थापना करना सुनिश्चित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना: पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत लघु कृषि मशीनों पर 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 95 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है

एसएमएएम के तहत वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक 9,404.47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से देशभर के किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत 27,554 कस्टम हायरिंग सेंटर, 646 हाई-टेक हब तथा 25,608 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व वाले लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2020-21 में 2.07 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2.32 लाख हो गई, जो कृषि मशीनीकरण के विस्तार और योजना की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है।

यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण की व्यवस्था पर आधारित है। अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी का अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 निर्धारित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तपोषण की यह व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि यांत्रिकीकरण को व्यापक स्तर पर अपनाने में सहायक है।

नवाचार को बढ़ावा: एसएमएएम के माध्यम से ड्रोन आधारित कृषि का बड़े पैमाने पर विस्तार

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) के तहत खेती-बाड़ी कार्यों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 52.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देशभर में व्यापक स्तर पर फील्ड प्रदर्शन आयोजित कर कृषि में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के सहयोग से 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 'किसान ड्रोन' के 40,928 प्रदर्शन आयोजित किए। इन प्रदर्शनों में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पोषक तत्वों, उर्वरकों एवं कृषि-रसायनों (एग्रो-केमिकल्स) के छिड़काव पर विशेष ध्यान दिया गया। ड्रोन आधारित कृषि को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए एसएमएएम के तहत ड्रोन की खरीद एवं उनके प्रदर्शन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसे पात्र संस्थानों को इन उद्देश्यों के लिए प्रति ड्रोन 10 लाख रुपये तक की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ड्रोन खरीदने के लिए 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, सेवा मॉडल के माध्यम से ड्रोन का उपयोग करने वाली एजेंसियों को प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपये तक का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, एसएमएएम समावेशी कृषि मशीनीकरण पर विशेष जोर देता है और कुल आवंटित निधि का 30 प्रतिशत महिला किसानों के लिए निर्धारित करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य कृषि मशीनों तक उनकी पहुंच बढ़ाना तथा मशीनीकृत कृषि पद्धतियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधा, दूसरा गले में... गाड़ी बढ़ते ही मौत! नगर निगम कर्मचारी का कूड़ा वाहन में मिला शव

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। बुधवार सुबह कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में एक संविदाकर्मी का शव मिला। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मुकेश पासवान के रूप में हुई है, जो नगर निगम में संविदा पर ड्राइवर के तौर पर कार्यरत था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि, मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे जब लोग पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मुकेश का शव पड़ा था। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा पास के एक पेड़ से बंधा था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही मृतक के परिवार, पत्नी और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है।

दो महीने पहले की थी शादी

जांच में सामने आया है कि मुकेश पासवान गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ का रहने वाला था। करीब दो महीने पहले उसने पड़ोसी गांव की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि दोनों अलग-अलग जाति से थे और इस शादी से दोनों परिवार नाराज थे। पारिवारिक विरोध के कारण दंपती गोरखपुर शहर में किराए के मकान में रह रहे थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शादी के बाद दंपती पर किसी तरह का मानसिक या पारिवारिक दबाव तो नहीं था।

बेतियाहाता के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों ने सुबह सूचना दी थी कि एक चालक ने आत्महत्या कर ली है। उनके अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि युवक ने पहले नायलॉन की रस्सी पेड़ से बांधी, फिर उसका दूसरा सिरा अपने गले में बांधकर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे गला कसने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती सूचना आत्महत्या की मिली थी, लेकिन परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बाद मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस रहस्यमयी मौत ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रधान की लापरवाही से भवानीपुर स्कूल के बाहर जलभराव

» हयूमन पाइप बनी शोपीस, नहीं बनी नाली, अभिभावकों में आक्रोश

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। ब्लॉक बल्दीराय के प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर बाउंड्रीवॉल के बाहर गंदे पानी का जलभराव स्कूली बच्चों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। हैंडपंप से निकलने वाले पानी के कारण बाउंड्री के बाहर एक बड़ा गड्ढा तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल परिसर के ठीक सामने गंदा पानी भरा हुआ है। जल निकासी के लिए एक ह्यूमन पाइप तो डाली गई है, लेकिन उसे नाली से जोड़ा नहीं गया है। परिणामस्वरूप बरसात और हैंडपंप का सारा पानी बहकर इसी गड्ढे में जमा हो रहा है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल गांव के प्रधान की कार्यशैली पर उठ रहा है। पंचायती राज अधिनियम के तहत गांव की साफ-सफाई, नाली निर्माण और जल निकासी की जिम्मेदारी सीधे ग्राम पंचायत और प्रधान की होती है। लेकिन भवानीपुर में जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। ग्रामीणों व स्कूली बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि 15 वें वित्त आयोग और राज्य वित्त से हर साल पंचायत को साफ-सफाई के लिए फंड मिलता है, इसके बावजूद स्कूल के बाहर नाली और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभिभावकों का आरोप है कि कई बार मौखिक शिकायत करने पर भी प्रधान की तरफ से सिर्फ बजट नहीं है और हो जाएगा कहकर टालमटोल की जाती रही। रोज सैकड़ों बच्चे इसी कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल आते-जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गंदा पानी अब मच्छरों का अड्डा बन गया है। यहां से उठने वाली बदबू और बरसात में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अभिभावकों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

शिक्षा विभाग का काम स्कूल में पढ़ाई कराना है, लेकिन गांव की बुनियादी सुविधाएं देना पंचायती राज विभाग का दायित्व है। भवानीपुर का यह मामला इस बात को उजागर करता है कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाएं और फंड किस तरह लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों ने खंड विकास अधिकारी से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कराई जाए और लापरवाह प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही 15 दिन के अंदर स्कूल के बाहर पक्की नाली बनवाकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे ब्लॉक का घेराव करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में हल्का सेक्रेटरी प्रियंका साहू से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रधान से बात कर समस्या का निदान करवा दिया जाएगा.

डीएम का आदेश भी बेअसर

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। कलेक्ट्रेट में सब कुछ ठीक-ठाक है या फिर नियमों की आड़ में कोई बड़ा खेल चल रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद महीनों से अटैच सरकारी वाहनों की जानकारी देने से जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत 25 अप्रैल 2026 को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के प्रयोग में चल रहे वाहनों की सूची और उनके वाहन नंबर मांगे गए थे। इस पर जिलाधिकारी कार्यालय ने 12 मई 2026 को प्रभारी अधिकारी नजारत को समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने का स्पष्ट निर्देश दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि 14 जुलाई 2026 तक न सूचना दी गई और न ही आदेश के अनुपालन की जहमत उठाई गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी जानकारी है जिसे सार्वजनिक करने से अधिकारी डर रहे हैं? यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो सूचना देने में दो महीने से अधिक की देरी क्यों।सूत्रों के अनुसार अधिकारियों से अटैच वाहनों के मामले में नियमों की अनदेखी किए जाने की आशंका है। यदि पूरी सूची सार्वजनिक होती है तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। चर्चा यह भी है कि इस पूरे मामले में नाजिर अलेंद्र सिंह की भूमिका की भी जांच की मांग उठ सकती है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह मामला केवल सूचना देने में देरी का नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता का भी है। जब जिलाधिकारी के लिखित आदेश का पालन कराने में ही विभाग नाकाम दिखाई दे तो आम नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई की क्या स्थिति होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा में नशे का हाई वोल्टेज ड्रामा! सड़क पर चादर ओढ़कर सोया शराबी, महिला ने काटा हंगामा

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कुछ घंटों के अंतराल में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नशे में हंगामे की घटनाएं सामने आई है। एक तरफ सूरजपुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत व्यक्ति सड़क के बीचों बीच चादर ओढ़कर सो गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दादरी थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी में नशे में धुत महिला ने सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया। पुलिस व स्थानीय लोगों से अभद्रता की। दोनों घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहला मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के क्राउन प्लाजा होटल के पास का है। यहां एक व्यक्ति दिनदहाड़े सड़क के बोचो-बीच चादर ओढ़ कर सो गया। आसपास से वाहन गुजराते रहे लेकिन वह बेखबर पढ़ रहा। राहगीरों ने पहले उसे उठाने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सड़क से हटाया। जांच में पता चला कि उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की।

नशे में धुत महिला का हंगामा

दूसरी घटना दादरी कोतवाली क्षेत्र के म्यु सेक्टर 2 स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट की है। यहां एक महिला नशे की हालत में सड़क पर बैठ गई, जिससे समिति के लोगों और स्कूली बसों की आवाजाही प्रभावित हुई। लोगों ने समझाने की कोशिश की तो महिला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। सूचना पर पुलिस का भी उसने सहयोग नहीं किया और अपना नाम पता बताने से इनकार कर दिया। बाद में महिला ने पैसे ना होने के बाद कही, जिसके बाद समिति के लोगों ने उसे 500 रुपए देकर ऑटो से रवाना कर दिया।

दो घटनाएं एक जैसी चिंता

दोनों घटनाएं अलग-अलग थाना क्षेत्र की है लेकिन एक समान तस्वीर पेश करती है। सार्वजनिक स्थानों पर नशे की हालत में इस तरह का व्यवहार न केवल संबंधित व्यक्ति की जान को खतरे में डालता है, बल्कि रहागीरों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है। इन घटनाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और उससे निपटने के लिए प्रभारी कार्रवाई की जरूरत को फिर से सामने ला दिया है। वहीं दोनों मामलों में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है।

चौकिया धाम में 10 हजार श्रद्धालुओं ने माथा टेका

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बुधवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने पर मां श्री शीतला धाम में सुबह 4 बजे से मंगला आरती दर्शन करने के लिए भक्त कतार में लग गर्भ ग्रह के कपाट खुलने का इंतजार करते रहे । सुबह 5:30 गर्भ ग्रह का कपाट खुलने पर मां शीतला की महारानी का आज प्रथम नवरात्र के दिन मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना मंदिर के महंत विवेकानंद ने मंगला आरती कर प्रारंभ की तत्पश्चात मां के सभी भक्तों ने बारी बारी से मां का दर्शन प्राप्त अपनी मनोकामना पूर्ति और माता जी के आशीर्वाद की प्रार्थना कर निकास द्वारा से निकलते रहे अनेक भक्तों ने अपनी कामना की सिद्धि के लिए हवन यज्ञ भी कराया । श्रद्धालु मां श्री शीतला जी के दर्शन के बाद गर्भ ग्रह के पीछे स्थित भगवान विष्णु के मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान मां श्री शीतला जी के कुंड के पास स्थित बाबा काल भैरवनाथ गर्भ ग्रह के पूर्व में स्थित बाबा बजरंगबली और मां काली के दर्शन कर अपने अपने गंतव्य और मां विंध्यवासिनी दर्शन के लिए प्रस्थान करते रहे । गुप्त नवरात्रि की इस विशेष अवसर पर मानस में शीतला जी मंदिर के महंत ने बताया कि आज लगभग 10 हजार दर्शनाथियों ने मां श्री शीतला जी मंदिर में आकर मां के चरणों में मत्था टेका।

निवेश के नाम पर युवक से ₹24.47 लाख की साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

सुलतानपुर। जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। शहर के दरियापुर (इलाहाबाद रोड) निवासी शिवम गुप्ता से विदेशी गारमेंट ब्रांड में निवेश कर कई गुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने ₹24,47,639 की ठगी कर ली। पीड़ति की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, शिवम को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया कि न्छफ्स्ब भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षक मुनाफा दे रही है। भरोसा दिलाने के लिए उसे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया, जहां बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। इसके बाद एक फर्जी वेबसाइट पर उसकी आईडी बनाकर निवेश की गई रकम और उस पर बढ़ता हुआ काल्पनिक मुनाफा दिखाया जाने लगा।

आलीशान गेट, चमचमाती सड़कें और फैंसी लाइटें...गोवर्धन की 40 एकड़ की इस कॉलोनी पर चला बुलडोजर

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। मथुरा के छाता-गोवर्धन रोड पर धेनू वाटिका (जेएसकेएस फेस-3) के नाम से काटी जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

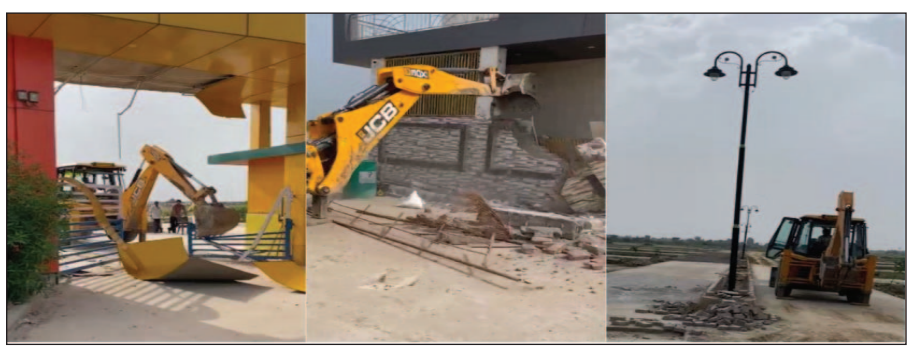

प्राधिकरण के अनुसार, अरविंद झा और अमित अतरी नामक व्यक्तियों द्वारा छाता-गोवर्धन रोड पर स्थित गांव सांखी क्षेत्र में लगभग 40 एकड़ भूमि पर बिना किसी अनुमति के बाउंड्रीवाल का निर्माण और प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। यह कृत्य उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन था। पूर्व में, 5 जून 2023 को इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन भू-माफियाओं ने प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज किया।

मंगलवार को उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने बरसाना पुलिस के सहयोग से इस अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान, कॉलोनी का बेहद आलीशान प्रवेश द्वार, जिसे अवैध रूप से बनाया गया था, उसे भी ढहा दिया गया। इसके अतिरिक्त, कॉलोनी के भीतर बनाई गई सीमेंट की सड़कें और उनके किनारे लगाई गई सुंदर स्ट्रीट लाइटें भी उखाड़ दी गईं। प्रशासन ने इस अवैध निर्माण के तहत बने एक मकान को भी ध्वस्त कर दिया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी। इस कार्रवाई से उन सभी लोगों को चेतावनी मिली है जो सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य शहरी नियोजन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना और आम जनता को अवैध निर्माणों के जाल में फंसने से बचाना है। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल अवैध निर्माणों पर अंकुश लगता है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी प्रशासन पर बढ़ता है।

चलती बस में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, मां की सतर्कता ने पकड़ा हैवान, पुलिस ने भेजा जेल

आर्यावर्त संवाददाता

चित्रकूट. चित्रकूट जिले में प्रयागराज से गांव जा रही एक रोडवेज बस में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।

यह घटना रामनगर के पास हुई है, जब एक युवक ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर दुष्कर्म किया। बच्ची से कुकृत्य करने की बात मेडिकल रिपोर्ट में भी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

रोडवेज बस से अपने गांव जा रही थी महिला

मामले में जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। बता दें कि एक महिला अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ प्रयागराज से करीब बारह बजे रोडवेज बस से अपने गांव जा रही थी। रास्ते में रामनगर के पास उसकी बगल की सीट पर मानिकपुर के गोविंद नगर निवासी राज किशोर बैठा था।

खिलाने के बहाने अपनी गोद में बिठाया

राज किशोर ने बच्ची को खिलाने के बहाने अपनी गोद में बिठा लिया। उसने बच्ची के कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया, जिससे बच्ची के निजी अंग से खून बहने लगा और वह दर्द से कराहने लगी। मां ने यह सब देखने के बाद बस परिचालक को जानकारी दी।

आरोपी को अगरहुडा के पास से गिरफ्तार किया

परिचालक को जानकारी देने के बाद मां ने रैपुरा थाना के सामने बस रुकवाकर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। निगरानी की मदद से आरोपी राज किशोर को अगरहुडा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से कुकृत्य की पुष्टि हुई है। परिजनों को जल्द न्याय दिलाने के लिए यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा।

लेखपाल के खिलाफ धमकी देने के मुदकमा

जौनपुर। न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश पर चकबंदी लेखपाल धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।जफराबाद थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी उर्मिला देवी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया के दौरान लेखपाल धर्मेंद्र सिंह ने उनकी सड़क किनारे की जमीन सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया था। इसके एवज में उर्मिला देवी ने लेखपाल को 20 हजार रुपए दिए थे।उर्मिला देवी के मुताबिक, बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई है। उन्हें इसके बदले ऊसर भूमि में एक चक आवंटित किया गया था। उर्मिला देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि पैसे वापस मांगने गईं, तो लेखपाल ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारकर बोरे में भरकर नदी में फेंकने की धमकी दी।

व्यापार समझौते को लेकर किया प्रदर्षन

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भारतीय किसान मजदूर जनसेवा यूनियन ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को तत्काल रद्द करने की मांग की है। यूनियन के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में देश बचाओ मोर्चा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।संगठन ने इस समझौते को किसानों, खेत मजदूरों और देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बताया है। जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के पशुपालकों, छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों तथा खाद्य एवं आर्थिक संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव

डालेगा।संगठन ने इस समझौते को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया है और स्पष्ट किया है कि इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बचाओ मोर्चा ने भारत सरकार से इस मुक्त व्यापार समझौते को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है, ताकि देश के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा हो सके। मोर्चे ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस मांग की अनदेखी करती है, तो देशभर में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।

गलती से एसिड पी ले तो शरीर में क्या होता है, बचाव के लिए तुरंत क्या करें, एक्सपर्ट ने बताया

गलती से एसिड पी जाए तो शरीर में क्या होता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हापुड़ में ज्वैलरी शॉप में बैठी एक लड़की ने गलती से पानी समझकर एसिड को पी लिया। बताया जा रहा है कि लड़की ने जिस बोतल से पानी पीया उसमें पहले से एसिड मिला हुआ था। छोटी सी ये गलती उसे अस्पताल ले गई जहां उसकी कंडीशन गंभीर बताई जा रही है। ऐसा अक्सर होता है और इस सिचुएशन में तुरंत क्या करना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। टीवी9 ने डॉक्टर नूपुर जैन (कंसलटेंट फिजिशियन, कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा) से खास बातचीत की।

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसी ने गलती से एसिड या टॉयलेट क्लीनर पी लिया है तो सबसे पहले उस इंसान को पैनिक नहीं करना चाहिए। इसको हल्के में भी नहीं लेना है।

क्या है एसिड पीने का पूरा मामला

लड़की के एसिड पीने का मामला हापुड़ के शाम नगर कोतवाली क्षेत्र के अर्जुन नगर का है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि महिला और उसकी लड़की ज्वैलरी खरीदने के लिए दुकान पर आए थे। पीड़ित लड़की ने प्यास लगने पर दुकानदार से पानी मांगा। दुकानदार पर आरोप है कि उसे पानी में तेजाब मिली हुई बोतल उसे थमा दी। बताया जा रहा है कि ज्वैलरी शॉप मालिक ने पास की कन्फेक्शनरी शॉप से एक ब्रांड की बोलत मंगाई।

कर्मचारी ने यही बोतल युवती को दी। उसने तेज प्यास के चलते बोलत खोली और पानी समझकर पी लिया। लड़की को इसे पीते ही अजीब लगा और उसकी चीख निकल गई। तबीयत बिगड़ने पर लड़की को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया।

गलती से एसिड पी लिया जाए तो क्या होता है?

एसिड पी जाने से मुंह, गला, फूड पाइप और यहां तक की हमारा पेट भी जल सकता है। इसके लक्षण जलन, निकलने में तकलीफ, बहुत ज्यादा थूक आना, उल्टियां लगना, खून की उल्टी, पेट में दर्द और अगर गला सूज गया है तो सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है।

तुरंत क्या करना है

सबसे पहले थोड़ा-थोड़ा पानी पिएं और नजदीकी अस्पताल में जाना है।

हमें उल्टी करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अंदर गए एसिड को ऐसे निकाला जा सकता है। इससे और नुकसान हो सकता है। इस कंडीशन में फिर से एसिड फूड पाइप में जाकर बर्न को सीवियर कर सकता है।

इस कंडीशन में बेकिंग सोडा, नींबू जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए, लोग एसिड को न्यूट्रिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर केमिकल रिएक्शन से और बर्न हो सकता है।

पेशेंट बेहोश है या फिर कुछ निगल नहीं पा रहा है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।

सबसे जरूरी है कि एसिड को निगलना एक बेहद बिगड़ी हुई मेडिकल कंडीशन है।

फोलिक एसिड ही नहीं.....प्रेगनेंसी में ये पोषक तत्व भी हैं जरूरी, एक्सपर्ट ने बताया

मां बनना एक खूबसूरत एहसास है लेकिन इससे पहले शरीर में कई बदलाव होते हैं। इसलिए हेल्थ को लेकर काफी सीरियस होना जरूरी है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर को पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। देखा जाए तो बेबी प्लान करने से कंसीव करने तक महिलाओं को गायना फोलिक एसिड लेने की सलाह देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में और भी कई दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। डॉ। मितुल गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कोकून हॉस्पिटल, जयपुर) का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का शरीर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मेहनत करता है।

इस समय बेबी का विकास, मां की ऊर्जा, खून की पर्याप्त मात्रा, हड्डियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक सही पोषण पर निर्भर करती है। हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, लेकिन इन नौ महीनों में कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं, जिनकी जरूरत हर होने वाली मां को होती है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सबसे जरूरी 7 पोषक तत्वों के बारे में।

पति ने ऑनलाइन मंगाया मर्डर वेपन।।। इंदौर में पत्नी की हत्या के बाद नहाया, खून से सने कपड़े नाली में बहाए; बेटी बोली- 'पापा को कड़ी सजा मिले'

प्रेगनेंसी में बेहद जरूरी हैं ये 7 पोषक तत्व

फोलिक एसिड- प्रेगनेंसी के शुरुआती तीन महीनों में फोलिक एसिड बेहद जरूरी होता है। यह बेबी के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में मदद करता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर प्रेगनेंसी की प्लानिंग के समय से ही फोलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ इसके अच्छे स्रोत हैं।

आयरन (खून की कमी से बचाए, ऊर्जा बढ़ाए)- प्रेगनेंसी के दौरान मां और बेबी दोनों के लिए शरीर को अधिक खून की जरूरत होती है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी और एनीमिया हो सकता है। पालक, गुड़, अंडा, चिकन और मछली आयरन के अच्छे स्रोत हैं।

कैल्शियम (मां और बेबी दोनों की हड्डियों के लिए जरूरी)- कैल्शियम बेबी की हड्डियों और दांतों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यह मां की हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखता है। अगर शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता, तो बेबी की जरूरत पूरी करने के लिए मां की हड्डियों से कैल्शियम लिया जा सकता है। दूध, दही, पनीर, रागी और हरी सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं।

विटामिन डी (कैल्शियम का पूरा फायदा दिलाए)- विटामिन D शरीर में कैल्शियम के बेहतर अवशोषण में मदद करता है। यह हड्डियों की मजबूती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। धूप इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा अंडा, फोर्टिफाइड दूध और फैटी फिश से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है।

प्रोटीन (बेबी की बढ़त और मां की सेहत के लिए)- प्रोटीन बेबी के अंगों, मांसपेशियों और शरीर के अन्य हिस्सों के विकास के लिए जरूरी है। यह प्रेगनेंसी के दौरान मां के शरीर में होने वाले बदलावों को भी सहारा देता है। दाल, अंकुरित अनाज, पनीर, अंडा, मेवे और बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।

ओमेगा-3 (दिमाग और आंखों के बेहतर विकास के लिए)- ओमेगा-3 फैटी एसिड, खासकर डीएचए (DHA), बेबी के दिमाग और आंखों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखरोट, चिया सीड्स और कम पारे वाली मछलियां इसके अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट ले सकती हैं।

आयोडीन (थायरॉयड और मस्तिष्क के लिए जरूरी)- आयोडीन थायरॉयड को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो बेबी के मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक, दूध से बने उत्पाद और अंडा इसके अच्छे स्रोत हैं। प्रेगनेंसी में स्वस्थ रहने का मतलब ज्यादा खाना नहीं, बल्कि सही और पौष्टिक भोजन करना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय पर सप्लीमेंट लें और अपने रोज़ाना के भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें। यही स्वस्थ मां और स्वस्थ बेबी की मजबूत नींव है।

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है मखाना, जानिए किन लोगों को करना चाहिए परहेज

वैसे तो मखाना काफी फायदेमंद लेता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। यहां हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे, जिन्हें मखाने खाने से परहेज करना चाहिए।

मखाना को सुपरफूड माना जाता है और यह पोषण से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। यही वजह है कि वजन घटाने से लेकर डायबिटीज कंट्रोल और दिल की सेहत तक के लिए मखाने को हेल्दी स्नैक के रूप में खाने की सलाह दी जाती है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए मखाना फायदेमंद नहीं होता? कुछ लोगों के लिए इसका अधिक सेवन नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। खासकर जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी या कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियां हैं, उन्हें मखाना खाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों को मखाना खाने से परहेज करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण हैं।

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए मखाना

1. जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है

मखाने में फाइबर होता है, लेकिन अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए और पानी कम पिया जाए, तो यह कब्ज की समस्या बढ़ा सकता है। जिन लोगों का पाचन पहले से कमजोर है, उन्हें सीमित मात्रा में ही मखाना खाना चाहिए।

2. पाचन संबंधी समस्या वाले लोग

अगर आपको गैस, अपच, पेट फूलना या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो ज्यादा मात्रा में मखाना खाने से परेशानी बढ़ सकती है। इसे हल्का भूनकर और सीमित मात्रा में खाना बेहतर माना जाता है।

3. एलर्जी की समस्या वाले लोग

कुछ लोगों को मखाने से एलर्जी हो सकती है। इसे खाने के बाद अगर त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन या सांस लेने में परेशानी महसूस हो, तो तुरंत इसका सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें।

4. किडनी के मरीज

मखाने में कुछ खनिज तत्व होते हैं। जिन लोगों को किडनी की गंभीर बीमारी है या जिन्हें डॉक्टर ने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी है, उन्हें मखाना खाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।

5. लो ब्लड प्रेशर वाले लोग

कुछ अध्ययनों के अनुसार, मखाना रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पहले से कम रहता है या वह बीपी की दवा ले रहा है, तो अधिक मात्रा में मखाना खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।

6. जरूरत से ज्यादा सेवन करने वाले लोग

किसी भी चीज की तरह मखाने का भी जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक मात्रा में खाने से पेट भारी होना, गैस, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

मखाना खाते समय रखें ये बातें

एक दिन में लगभग 25–30 ग्राम (करीब एक मुट्ठी) मखाना पर्याप्त माना जाता है।

इसे हल्का भूनकर खाना बेहतर रहता है।

अधिक नमक, मक्खन या घी मिलाकर खाने से इसके स्वास्थ्य लाभ कम हो सकते हैं।

यदि आप किसी गंभीर बीमारी या दवा पर हैं, तो नियमित सेवन से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें।

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर: गोल्ड बॉन्ड से हुई कमाई को छुपाना पड़ेगा भारी, जानिए आईटीआर में कैसे दें जानकारी

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR भरने वाले टैक्सपेयर्स को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) से मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स की सही जानकारी देनी होगी। जानें कि SGB के ब्याज, मैच्योरिटी पर रिडेम्पशन और मैच्योरिटी से पहले बिक्री पर टैक्स कैसे लगता है, इसके लिए कौन-से ITR शेड्यूल इस्तेमाल करने हैं, और बजट 2026 में किए गए बदलाव इस साल क्यों लागू नहीं होंगे।

असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। यदि आपने भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) स्कीम में निवेश किया है और उससे कमाई की है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई टैक्सपेयर्स ITR दाखिल करते समय SGB से होने वाली आय को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के नियम क्या हैं और आपको अपने रिटर्न में इसे कैसे दिखाना है।

SGB से होने वाली कमाई: दो हिस्सों में समझें टैक्स का नियम

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से निवेशकों को दो तरह से कमाई होती है—पहला, सालाना मिलने वाला ब्याज और दूसरा, बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर मिलने वाला कैपिटल गेन (Capital Gains)। इन दोनों पर टैक्स के नियम पूरी तरह अलग हैं:

1। सालाना मिलने वाले ब्याज पर टैक्स

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर निवेशकों को 2.5 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है, जो साल में दो बार (छमाही आधार पर) सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है।

टैक्स नियम: यह ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। यह आपकी सालाना आय में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब (Tax Slab) के अनुसार इस पर टैक्स लगता है।

ITR में कहां दिखाएं: इसे ITR फॉर्म में 'Income from Other Sources' (अन्य स्रोतों से आय) के हेड के तहत घोषित करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण बात: आरबीआई इस ब्याज पर कोई TDS (Tax Deducted at Source) नहीं काटता है, इसलिए कई निवेशक इसे रिटर्न में दिखाना भूल जाते हैं। यह एक बड़ी गलती है क्योंकि यह ट्रांजैक्शन आपके AIS (Annual Information Statement) में दर्ज होता है।

2। मैच्योरिटी और कैपिटल गेन्स पर टैक्स

टैक्स के लिहाज से SGB को सबसे बेहतरीन निवेश माना जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं:

8 साल की मैच्योरिटी पर: यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को पूरे 8 साल की मैच्योरिटी अवधि तक अपने पास रखते हैं, तो रिडेम्पशन के समय मिलने वाला पूरा मुनाफा (Capital Gains) 100% टैक्स-फ्री होता है। इस पर आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होता।

साल बाद प्री-मैच्योर रिडेम्पशन: 5 साल के बाद आरबीआई के साथ सीधे प्री-मैच्योर रिडेम्पशन करने पर भी व्यक्तिगत निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलती है।

स्टॉक एक्सचेंज पर बिक्री: यदि आप 8 साल पूरे होने से पहले अपने SGB को स्टॉक एक्सचेंज (NSE/BSE) पर बेचते हैं, तो यह मुनाफा टैक्स-फ्री नहीं होगा। होल्डिंग पीरियड के आधार पर इस पर शॉर्ट-टर्म (STCG) या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा।

SGB से हुई इनकम की जानकारी कैसे दें

SGB से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी, मामले के आधार पर, ITR-2, ITR-3 या ITR-4 में दिए गए संबंधित शेड्यूल में देनी होगी। SGB पर मिलने वाला सालाना 2.5 फीसदी ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है और इसकी जानकारी 'Schedule OS' (अन्य स्रोतों से आय) में देनी होगी।

इस ब्याज पर निवेशक के लागू इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। चूंकि सरकारी सिक्योरिटीज को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 193 के तहत TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) से छूट मिली हुई है, इसलिए इस ब्याज पर स्रोत पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा।

कैपिटल गेन्स की जानकारी देना इस बात पर निर्भर करता है कि बॉन्ड को कैसे बेचा या भुनाया गया है। अगर ओरिजिनल सब्सक्राइबर मैच्योरिटी पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के पास बॉन्ड को रिडीम (भुनाता) करता है, तो असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू नियमों के तहत कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगेगा।

ITR फाइल करते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

AIS और TIS को क्रॉस-चेक न करना: रिटर्न भरने से पहले अपना Annual Information Statement (AIS) जरूर डाउनलोड करें। आरबीआई द्वारा आपको दिया गया ब्याज इसमें पहले से दिखाई देता है। अगर आपके ITR और AIS के आंकड़ों में अंतर मिला, तो ऑटोमैटिक नोटिस आ सकता है।

एक्सचेंज पर बेचे गए बॉन्ड को छुपाना: अगर आपने शेयर बाजार के जरिए SGB को मैच्योरिटी से पहले बेचा है, तो उसे आईटीआर में 'Capital Gains' शेड्यूल के तहत दर्ज करें। लिस्टेड सिक्योरिटीज के नियमों के अनुसार उचित इंडेक्सेशन या टैक्स रेट का लाभ लेते हुए इसकी गणना करें।

टैक्स-फ्री मैच्योरिटी अमाउंट को न दिखाना: भले ही 8 साल पूरे होने पर मिला पैसा पूरी तरह टैक्स-फ्री है, फिर भी इसे आईटीआर के 'Exempt Income' (कर-मुक्त आय) वाले शेड्यूल में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि आपकी कुल संपत्ति और कमाई का सही ब्योरा विभाग के पास रहे।

नियमों का जरूर करें पालन

डिजिटल ट्रैकिंग के इस दौर में आयकर विभाग के पास आपके हर वित्तीय लेनदेन की सटीक जानकारी होती है। इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से मिले ब्याज को 'Income from Other Sources' में दिखाकर और मैच्योरिटी के मुनाफे को नियमानुसार रिपोर्ट करके आप किसी भी तरह के टैक्स झंझट और पेनाल्टी से बच सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक बॉन्ड सीरीज हैं, तो बेहतर होगा कि फाइलिंग से पहले अपने बैंक स्टेटमेंट और SGB होल्डिंग सर्टिफिकेट का मिलान कर लें।

बजट 2026 के बदलाव अगले साल से लागू होंगे

2026 के बजट में एक अहम बदलाव यह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिडेम्पशन (भुनाए जाने) पर कैपिटल गेन्स में छूट सिर्फ 'ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स' (शुरुआती खरीदारों) को ही मिलेगी, जिन्होंने RBI द्वारा जारी किए जाने के समय बॉन्ड खरीदे या उनमें निवेश किया था और मैच्योरिटी तक उन्हें अपने पास रखा था।

इसके अलावा, जिन निवेशकों ने सेकेंडरी मार्केट से SGBs खरीदे हैं, उन्हें अब यह छूट नहीं मिलेगी। नतीजतन, ऐसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिडेम्पशन से होने वाला कोई भी फ़ायदा टैक्सेबल होगा और उसे शेड्यूल कैपिटल गेन्स के तहत रिपोर्ट करना होगा।

हालांकि, ये बदलाव सिर्फ असेसमेंट ईयर 2027-28 से लागू होंगे, जब नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पूरी तरह से लागू हो जाएगा। सही शेड्यूल के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ब्याज और कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग करने से सही टैक्स फाइलिंग सुनिश्चित करने और बेवजह के नोटिस व कानूनी पेचीदगियों से बचने में मदद मिलेगी।

भारत-यूके एफटीए से ब्रिटिश सामान होंगे सस्ते, भारतीय निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) बुधवार से प्रभावी हो जाएगा। इससे एक तरफ देश के घरेलू निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी तरफ भारतीय सामानों को यूके का बाजार मिलेगा।

इस समझौते के तहत, स्कॉच व्हिस्की, जिन, चॉकलेट, बिस्कुट और कॉस्मेटिक्स जैसे कई ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ 15 जुलाई से कम होने लगेंगे। हालांकि, कुछ चीजों पर ड्यूटी में कटौती आने वाले सालों में धीरे-धीरे लागू की जाएगी।

वहीं, भारतीय निर्यातकों को लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जिसमें यूके को होने वाले देश के निर्यात की लगभग पूरी वैल्यू शामिल है।

टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, खेल का सामान और खिलौने जैसे ज्यादा लेबर वाले सेक्टर को इससे सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है।

इसी तरह, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटो पार्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल को भी बेहतर मार्केट एक्सेस से फायदा होगा।

ये नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने जारी किए थे। इनमें यह तय करने का तरीका बताया गया है कि क्या सामान समझौते के तहत खास टैरिफ सुविधा के लिए योग्य है या नहीं, और साथ ही निर्यातकों और आयतकों के लिए जरूरी नियमों की जानकारी भी दी गई है।

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सीईटीए से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और इनोवेशन में सहयोग बढ़ेगा और साथ ही व्यापार और पेशेवरों के लिए नए मौके बनेंगे।

उन्होंने भारतीय कंपनियों से कहा कि वे यूके की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें और इस समझौते को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदलें।

इससे पहले जून में, केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि यह अहम समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे बिजनेस को ग्लोबल स्तर पर आगे बढ़ने और नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा, साथ ही आम लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान सही कीमत पर मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि यूके के प्रीमियम मार्केट तक पहुंचने से महिला उद्यमियों, युवाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए आकर्षक ग्लोबल मौके बनेंगे, और साथ ही भारत के मुख्य हितों से समझौता किए बिना कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सकेगा।

14 दौर की बातचीत के बाद 24 जुलाई, 2025 को साइन किए गए सीईटीए में 30 चैप्टर हैं, जिनमें सामान, सर्विस, डिजिटल व्यापार, फाइनेंशियल सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सरकारी खरीद शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर टैरिफ कम करेगा या खत्म कर देगा, जिसमें से 85 प्रतिशत अगले दशक में पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री हो जाएंगी।

ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ शुरू में 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा और फिर 10 सालों में यह 40 प्रतिशत तक आ जाएगा, जबकि ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर ड्यूटी को कोटा-आधारित सिस्टम के तहत धीरे-धीरे कम किया जाएगा।

यह समझौता यूके में कुछ समय के लिए काम करने वाले योग्य भारतीय प्रोफेशनल्स को 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन' के जरिए राहत भी देता है, जिससे वे एक तय समय के लिए दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने से बच सकते हैं।

रिफाइनरियों के ठप होने से दुनिया में ईंधन संकट, भारत के पास 23 रिफाइनरी

वॉशिंगटन, एजेंसी। दुनिया के सामने इस वक्त कच्चे तेल की कमी उतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी इसे पेट्रोल और डीजल में बदलने की है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही अर्थशास्त्रियों की चिंता कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर थी। लेकिन अब अमेरिका और ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और तेल की कीमतों के 80 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बीच एक नया और कहीं ज्यादा गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यह संकट है पेट्रोल-डीजल बनाने की दुनिया की क्षमता का घटना।

फारस की खाड़ी से जो करोड़ों बैरल तेल बाहर आ रहा है, वह अपने आप में किसी काम का नहीं है। कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल (ATF) और डामर में बदलने के लिए रिफाइनरियों की जरूरत होती है। लेकिन फिलहाल वैश्विक रिफाइनिंग क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के दर्जनों रिफाइनरियों पर हमला किया है, यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा ठिकानों को ड्रोन से तबाह किया है। साथ ही ज्यादा तापमान के कारण रिफाइनरियों के कूलिंग सिस्टम का फेल हो गए हैं। इन सबने मिलकर ग्लोबल रिफाइनिंग चेन को तोड़ दिया है। जेपी मॉर्गन के डेटा के मुताबिक, दुनिया भर की रिफाइनरियां युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में हर दिन 84 लाख बैरल कम कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में ईंधन का उत्पादन 10% तक गिर गया है।

भारत की स्थिति क्या है?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (भारत सरकार) के ताजा और प्रामाणिक आंकड़ों (FY 2025-26) के अनुसार भारत की स्थिति इस प्रकार है

भारत के पास कितना तेल है और कितनी खपत होती है?

भारत के पास अपने भूभाग में कच्चे तेल का सीमित भंडार है, जिससे सालाना सिर्फ 28 मिलियन मेट्रिक टन (MMT) तेल ही निकलता है। ये भंडार असम, मुंबई हाई और राजस्थान में हैं। लेकिन भारत की रिफाइनरियां इतनी बड़ी हैं कि वे विदेशों से कच्चा तेल मंगाकर सालाना 258 MMTPA से अधिक तेल प्रोसेस करती हैं। भारत में कुल 23 रिफाइनरियां हैं, जिनमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र की हैं।

खपत के मामले में भारत में डीजल सबसे आगे है। देश की कुल तेल खपत (243.12 MMT) में करीब 39% हिस्सा अकेले डीजल का (94.17 MMT) और करीब 17.5% हिस्सा पेट्रोल का (42.16 MMT) है। देश भर में 1,03,023 से अधिक पेट्रोल पंप (रिटेल आउटलेट्स) इस विशाल मांग को पूरा करते हैं। जामनगर (गुजरात) स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है।

भारत का एनर्जी शील्ड

दुनियाभर में ईंधन संकट के बीच भारत की स्थिति अमेरिका और यूरोप से बेहतर क्यों है? इसके पीछे चार प्रमुख रणनीतिक कारण हैं...

1- सरप्लस रिफाइनिंग का होना

अमेरिका और यूरोप में जहां पुरानी रिफाइनरियां बंद हो रही हैं, वहीं भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता को लगातार बढ़ाया है। भारत अपनी घरेलू खपत (243 MMT) से कहीं अधिक (258+ MMT) रिफाइनिंग क्षमता रखता है। इसी कारण जब यूरोप और एशिया में डीजल-पेट्रोल का संकट पैदा हुआ, तो भारत के रिफाइंड उत्पादों के निर्यात ने वैश्विक बाजार को संभाला।

2- सप्लाई सोर्स का विविधीकरण

भारत ने खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अपने कच्चे तेल के सप्लायर देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 देश कर दी है। रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर उसे अपनी अत्याधुनिक रिफाइनरियों (जैसे जामनगर और वाडिनार) में प्रोसेस करने की रणनीति से भारत ने न सिर्फ अरबों डॉलर बचाए, बल्कि घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को भी स्थिर रखा।

3- एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) की सफलता

भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने (E20) का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। इससे देश को कच्चे तेल के आयात में ₹1.55 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और पेट्रोल की शुद्ध मांग पर दबाव कम हुआ है।

4। रणनीतिक तेल भंडार (SPR – फेज II)

संकट के समय के लिए भारत सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (ISPRL) के दूसरे चरण के विस्तार के लिए ₹5,597 करोड़ आवंटित किए हैं, ताकि किसी भी युद्ध या समुद्री नाकाबंदी की स्थिति में देश कम से कम 70 से 90 दिनों तक बिना रुके चल सके।

किन्नर के भेष में रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक, दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे से किया गिरफ्तार

ढाका, एजेंसी। भारत के ज्यादातर शहरों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसा ही एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया है, जो किन्नर के भेष में रह रहा था। उसके पास न तो वैध पासपोर्ट था और न ही वीजा। यहां तक की उसके पास कोई अन्य दस्तावेज भी नहीं था।

राजधानी दिल्ली में पुलिस ने 44 साल के एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर लंबे समय से भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहा था। वह दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में किन्नर का भेष बदलकर घूम रहा था। आरोपी को नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के फॉरेनर्स सेल द्वारा गैर-कानूनी विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए गए एक स्पेशल अभियान के दौरान पकड़ा गया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सुकांता चंद्र दास उर्फ माधुरी के तौर पर हुई है। सुकांता को 10 जुलाई को जहांगीरपुरी में भलस्वा फ्लाईओवर के नीचे से एक खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, वह भारत में रहने के लिए कोई वैध पासपोर्ट या वीजा या अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

पुलिस ने बताया कि विस्तृत जांच और तकनीकी पड़ताल से पुष्टि हुई कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। पूछताछ में आरोपी सुकांता ने कथित तौर पर माना कि रात में वह किन्नर का ड्रेस पहनकर निकलता था और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल रहता था।

फोन में मिली बांग्लादेशी पहचान

जांच के दौरान उसके पास से जब्त स्मार्टफोन में प्रतिबंधित IMO एप्लिकेशन इंस्टॉल पाया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि फोन की गैलरी में बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान से जुड़े दस्तावेजों की कई तस्वीरें थीं। यह ऑपरेशन इंस्पेक्टर विपिन कुमार की अगुवाई और एसीपी रंजीत ढाका की देखरेख में फॉरेनर्स सेल की एक टीम ने चलाया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आरोपी को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद कानून के मुताबिक उसे वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले कर्नाटक के मंगलुरु में अवैध प्रवासियों के खिलाफ नई कार्रवाई में 11 और बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मंगलुरु पुलिस ने 11 और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है जो कथित तौर पर यहां अवैध रूप से रह रहे थे। इसके साथ ही मंगलुरु में हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या 19 हो गई है।

ईरान-अमेरिका की जंग में पिस रहे भारतीय, होर्मुज में हुए हमले में अब तक 15 नाविक गंवा चुके हैं जान

तेहरान, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के पास कॉमर्शियल जहाजों पर भी हमले हुए। फरवरी से शुरू हुए इस तनाव के बीच 15 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। हाल ही में जब ईरान ने दो तेल टैंकरों, मोम्बासा बी (Mombasa B) और अल बह्या पर हमला किया। इसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल भी हो गए। इस हमले के बाद, भारत ने ईरान के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय में तलब किया। इनमें डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद होसैनी भी शामिल थे।

UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों जहाजों पर ओमान के समुद्री क्षेत्र में, होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी रास्ते से गुजरते समय हमला किया गया। शिपिंग कंपनी ADNOC L&S ने पुष्टि की कि दोनों बहुत बड़े तेल टैंकरों (VLCC) को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में जहाज के 8 क्रू सदस्य घायल हो गए, जिनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शामिल हैं। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ये ताजा हादसा उन घटनाओं की बढ़ती सूची का हिस्सा है, जिनमें भारतीय नाविक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे टकराव की चपेट में आ गए हैं। उसी दिन, ओमान के मुसन्दम प्रायद्वीप के पास पलाऊ के झंडे वाले टैंकर 'स्काईलाइट' पर हमले के बाद दो भारतीय नाविक मारे गए। होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय क्रू सदस्यों को ले जा रही लकड़ी की नाव (धाऊ) में आग लगने से एक भारतीय नाविक की मौत हो गई।

12 जुलाई को नाविक लापता

ओमान तट के पास साइप्रस के झंडे वाले कमर्शियल जहाज 'GFS गैलेक्सी' पर ईरान के हमले के बाद एक भारतीय नाविक लापता हो गया। बाद में ओमान की नौसेना ने जहाज से 10 भारतीय क्रू सदस्यों को बचाया।

14 जुलाई: भारतीय नाविक की मौत

मोम्बासा पर सवार एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। घायल क्रू सदस्यों में 6 भारतीय नागरिक थे, जबकि दो यूक्रेनी नागरिक थे।

ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल शिपिंग रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस इलाके से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हजारों भारतीय नाविक काम करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण उन पर खतरा बढ़ गया है।

अभिषेक की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत : आवाज का नमूना देने कोर्ट पहुंचे टीएमसी नेता

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी बुधवार को विधाननगर अदालत पहुंचे। दरअसल, उन पर आरोप है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर उन्होंने धमकी भरे भाषण दी। इसी के जांच के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना आवाज का नमूना देने के लिए पहुंचे है।

जांच एजेंसी के अनुरोध पर आवाज का नमूना देने के लिए विधाननगर एसडीजेएम अदालत की ओर से निर्धारित दो पिछली तारीखों पर वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को बनर्जी को इस उद्देश्य से 15 जुलाई को दोपहर में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

बनर्जी की पेशी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहां पास के साल्ट लेक स्थित अदालत परिसर के अंदर और आसपास भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। उनके वकील की याचिका पर, उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि डायमंड हार्बर सांसद को संबंधित अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने पर अंडे फेंकने या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

बता दें कि बनर्जी को 30 मई को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक दिवंगत पार्टी समर्थक के घर जाने पर विरोध का सामना करना पड़ा था।

बंगाल की बेटी को मिलेगा इंसाफ

13 साल पुराने कामदुनी केस की खुलेगी फाइल, मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचा पीड़ित परिवार

कोलकाता, एजेंसी। कामदुनी दुष्कर्म-हत्या पीड़िता के परिवार के सदस्य बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के 'जनता दरबार' कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ दिन पहले ही राज्य के भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने 13 साल पहले हुए अपराध की फाइलों को फिर से खोलने की बात कही।

2013 की कामदुनी घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दो प्रमुख चेहरे, तुम्पा कोयल और मौसमी कोयल, मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात के दौरान पीड़ित के परिवार के सदस्यों के साथ थे। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'जनता दरबार के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों पर उचित प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।'

अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर लोगों की शिकायतें सुनने और अधिकारियों

को उनका तुरंत निवारण करने के निर्देश देने के लिए अपना 'जनता दरबार' आयोजित करते आ रहे हैं। इस तरह का पहला साप्ताहिक कार्यक्रम 18 मई को आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अधिकारी ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा था कि नागरिक हर सप्ताह उनसे सीधे मिल सकेंगे।

2013 में, उत्तरी 24 परगना के कामदुनी में घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा को एक खेत में घसीटकर ले जाया गया। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका क्षत-विक्षत शव अगली सुबह मिला। इस घटना ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था।

कोर्ट ने क्या सजा सुनाई?

तीन साल बाद, एक सत्र न्यायालय ने इस मामले में तीन आरोपियों को मौत की सजा और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो आरोपियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और तीसरे दोषी को बरी कर दिया। इसने तीन अन्य दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को कम कर दिया था।

टीएमसी पर क्या आरोप लगाया?

अधिकारी ने आरोप लगाया था कि पूर्व टीएमसी सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मांग कर रही कामदुनी बलात्कार और हत्या पीड़िता के परिवार का विरोध कर रही थी। उन्होंने कहा था कि उनका प्रशासन उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करके मदद का हाथ बढ़ाएगा।

पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने की शिकायत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य ने अदालतों के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए और पुलिस ने अपराध की ठीक से जांच नहीं की। कामदुनी घटना के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस स्थान का दौरा किया था और उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों में माओवादी भी शामिल थे, इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना हुई थी।

माधुरी दीक्षित ने पति श्रीराम नेने के साथ साझा की रोमांटिक तस्वीर, लिखा- 'कुछ खास पल...'

माधुरी दीक्षित ने पति श्रीराम नेने के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। इसी के साथ माधुरी ने पति राम के लिए एक रोमांटिक नोट लिखकर प्यार जताया है।

बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कर फैंस का दिल जीत लिया है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने पति के लिए एक प्यारा संदेश भी लिखा है।

माधुरी दीक्षित ने ये तस्वीरें बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन के दौरान खिंचवाई थीं, जिन्हें उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर साझा कर फैंस का दिल जीत लिया है। इन तस्वीरों में माधुरी ने एक बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है। वहीं डॉ. श्रीराम नेने ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम नजर आ रहे हैं।

माधुरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। इस गुलाबी साड़ी में माधुरी ने कई दिलकश पोज देकर फैंस का दिल जीत लिया है। एक तस्वीर में माधुरी अपने पति राम को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं। इसी के अलावा कई तस्वीरों में माधुरी अपने डॉगी के साथ पोज देती हुई बेहद खुश दिख रही हैं।

माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने की शादी 17 अक्तूबर 1999 को हुई थी। डॉ. नेने अमेरिका में दिल के डॉक्टर हैं। शादी के बाद माधुरी अमेरिका के डेनवर में रहने लगी थीं। उनके दो बेटे हैं- एरिन और रयान। साल 2011 में यह पूरा परिवार वापस मुंबई शिफ्ट हो गया।

माधुरी दीक्षित हाल ही में 'मां बहन' फिल्म में नजर आईं। यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म है। इसमें माधुरी ने 'रेखा' नाम की एक मां का रोल निभाया है, जिसकी रसोई में अचानक एक लाश मिल जाती है। इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी और रवि किशन जैसे कलाकार भी हैं।

परिवार के साथ पहुंचीं प्रियंका, अनन्या से लेकर श्रीलीला ने लगाया विंबलडन में ग्लैमर का तड़का

टेनिस के सबसे बड़े आयोजनों में से एक विंबलडन 2006 अब खत्म हो चुका है। बॉलीवुड के कई खेल प्रेमी इस साल इसे देखने लंदन के इंग्लैंड क्लब पहुंचे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से लेकर अनन्या पांडे तक सेलेब्स स्टाईलिश अंदाज में विंबलडन देखते नजर आए। यहां देखें विंबलडन 2026 की कुछ खास तस्वीरें-

प्रियंका ने की परिवार के साथ शिरकत

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी विंबलडन देखने इंग्लैंड क्लब पहुंची। उनके साथ उनकी सास डेनिस जोनास और ससुर पॉल केविन जोनास भी थे। इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की। इस दौरान उन्होंने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थीं।

लाल ड्रेस में पहुंची अनन्या पांडे

एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी ग्रैंड स्लैम देखने पहुंची। इस दौरान एक्ट्रेस ने लाल राल्फ लॉरेन आउटफिट पहना था, जिसमें वह काफी ग्लैमरस दिखाई दे रही थीं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपना विंबलडन लुक फैंस के साथ साझा किया।

श्रीलीला ने चुराई लाइम लाइट

एक्ट्रेस श्रीलीला इस ग्रैंज स्लैम को एंजॉय करने लंदन गईं थीं। इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक नॉन फॉर्मल सूट में दिखाई दीं। फॉर्मल पैंट के ऊपर उन्होंने ओवर साइज कोट पहन रखा था। इसके साथ ही ब्लैक शेड्स उनपर काफी फब रहे थे।

कल्याणी प्रियदर्शन ने उठाया मैच का लुत्फ

एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन मैच इंजॉय करने लंदन पहुंची। एक्ट्रेस कैजुअल लुक में विंबलडन का लुत्फ उठाने पहुंची। इस दौरान वाइट ड्रेस में कॉफी पीते दिखाई दीं।

एक्ट्रेस आएशा खान भी हुईं शामिल

अभिनेत्री आएशा खान कई सेलिब्रिटीज की तरह विंबलडन देखने पहुंचीं। रेड कलर की ड्रेस में एक्ट्रेस मैच के दौरान ग्लैमर का तड़का लगाती दिखाई दीं।

जया कृष्णा घट्टामनेनी और राशा थडानी की फ़ल्मि श्रीनिवास मंगपुरम की रिलीज की तारीख से उठा पर्दा, 30 जुलाई को रिलीज़ होगी

जया कृष्णा घट्टामनेनी की फ़ल्मि श्रीनिवास मंगपुरम से वे बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं और यह फ़ल्मि 30 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज़ होगी। अजय भूपति के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक-एक्शन फ़ल्मि को एक अच्छा मौका मिला है क्योंकि इस दौरान किसी बड़े स्टार की फ़ल्मि रिलीज़ नहीं हो रही है। प्रोड्यूसर पी. किरण और प्रेजेंटर अश्विनी दत्त फ़ल्मि की चर्चा बनाए रखने के लिए ज़ोर-शोर से प्रमोशन करने की योजना बना रहे हैं। राशा थडानी इस फ़ल्मि से जया कृष्णा के साथ तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं।

30 जुलाई की तारीख का एक खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन 1999 में महेश बाबू की फिल्म राजकुमारुडु रिलीज़ हुई थी। पहले यह फिल्म 9 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने तारीख बदल दी ताकि यह अखिल की फिल्म लेनिन के साथ न टकराए। मोहन बाबू विलेन का रोल निभा रहे हैं, जिससे फिल्म में स्टार पावर जुड़ गई है। अजय भूपति ने तिरुपति-चित्तूर की पृष्ठभूमि में रोमांस, इमोशन और ज़बरदस्त एक्शन का मेल दिखाया है।

प्रमोशनल कंटेंट में जया कृष्णा की दमदार मौजूदगी और राशा के साउथ इंडियन लुक, एक्शन अवतार और डांस स्किल्स की तारीफ़ हो रही है। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का मुख्य विषय है। जीवी प्रकाश कुमार के संगीत और शानदार विज़ुअल्स ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही ट्रेलर से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है।

अजय भूपति ने युवा प्रेम को पूरी शिद्दत के साथ दिखाया है और कमर्शियल एलिमेंट्स व ज़मीनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखा है। मोहन बाबू का अहम रोल कहानी के टकराव को और मज़बूत बनाता है, जबकि राशा की बॉलीवुड में लोकप्रियता फिल्म की पहुँच बढ़ाने में मदद करती है। महेश बाबू के भतीजे के ज़रिए कृष्णा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, श्रीनिवासा मंगपुरम का लक्ष्य परिवार और एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक बेहतरीन डेब्यू फिल्म पेश करना है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com